कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिवशक्ति बक्सी

संपादक मंडल

सत्यपाल
संजीव कुमार सिन्हा

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDI : +91(11) 23387887

पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

भाजपा स्थापना दिवस (6 अप्रैल) पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी।

संसद में बहस

आम बजट 2012&13

राज्यसभा

अरुण जेटली..... 6
प्रभात झा..... 14
पीयूष गोयल..... 19

लोकसभा

जसवंत सिंह..... 25
यशवंत सिन्हा..... 27

अन्य

भाजपा स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम..... 30

बोफ़ा कथा

नींव का पत्थर

यह उन दिनों की बात है जब लाल बहादुर शास्त्री लोक सेवा मंडल के सदस्य बनाए गए। मंडल की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। इसके माफ़यम से वह राष्टौ निर्माण में युवकों की भागीदारी बढ़ाना चाहते थे। शास्त्री जी मितभाषी और संकोची स्वभाव के थे। वह हर व्यक्ति को सम्मान जरूर देते थे पर उनका उससे संवाद बेहद संक्षिप्त हुआ करता था। वह पत्र–पत्रिकाओं के संवाददाताओं से भी श्रयः दूरी बनाकर चलते थे जबकि लोक सेवा मंडल के और सदस्य तथा दूसरे नेता उनसे मिलकर अपने कार्यों का खूब बखान किया करते थे। पर शास्त्री जी नहीं चाहते थे कि उनकी तस्वीरें या साक्षात्कार आदि सिर्फ उनके रुतबे के कारण श्काशित होते रहें।

उनके एक सहयोगी ने एक बार उन्हें टोकते हुए कहा– शास्त्री जी, और नेता तो श्चार पाने के लिए तरह–तरह के हथकंडे अपनाते हैं, दावतें आदि देते रहते हैं पर आप तो सुनहरा अवसर हाथ में रहते हुए भी उसका लाभ नहीं उठाते। ऐसा क्यों?

इस पर शास्त्री जी गंभीर होकर बोले– भाई, जब लाला लाजपत राय जी ने मुझे लोक सेवा मंडल का सदस्य बनाया था तभी कहा था कि लोग ताजमहल के उजले और सुंदर पत्थरों को देखकर मंत्रमुग्फ़ा हो जाते हैं। मगर जिन नींव के मजबूत पत्थरों पर ताजमहल टिका हुआ है वहां किसी की नजर ही नहीं जाती। इसलिए तुम्हें श्चार–श्सार से दूर रहकर दिखने वाला नहीं, टिकने वाला पत्थर बनना है। मैं लाला जी की उसी सीख पर अमल करना चाहता हूं। शास्त्री जी की यह बात सुनकर उनका सहयोगी निरुद्वार हो गया।

जनवभारत टाइम्सफ

संकलन : मुकेश जैन

व्यंग्य चित्र

हमें लिखें...

सम्पादक के नाम पत्र

कमल संदेश

सादर आमंत्रित

आपकी राय एवं विचार

सम्पादक,
कमल संदेश
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66
सुब्रहमण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
ई-मेल:
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रिय पाठकगण

कमल संदेश (पाक्षिक) का अंक आपको नियमित मिल रहा होगा। यदि किन्हीं कारणवश आपको कोई अंक प्राप्त न हो रहा हो तो आप अपने प्रदेश कार्यालय को या हमें अवश्य सूचित करें।

-सम्पादक

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का परिवार भाव

संपादकीय

मफ्रय प्रदेश की भाजपा सरकार ने पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय प्रयास प्रारंभ करने की घोषणा की है। मैं संपादकीय भी इसलिए लिख रहा हूं, क्योंकि देश के सामने सभी बातें आती हैं, पर वह बात तो अवश्य आनी चाहिए जो देश की आम जनता को अच्छा लगे और सारा देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करे।

श्री शिवराज सिंह ने अपनी भाजपा सरकार की एक ऐसी योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत मफ्रयप्रदेश का प्रत्येक बुजुर्ग ञपुरुष/महिलाप पूरे देश के तीर्थाटन पर, जैसेकि बालाजी या फिर अजमेरशरीफ जाना चाहते हैं तो मफ्रयप्रदेश की भाजपा सरकार उनकी चिंता करेगी। 60 वर्षीय यदि हैं तो वे अकेले, यदि वे 65 वर्ष के हैं तो उनके साथ एक व्यक्ति सरकार की व्यवस्था से जा सकता है।

भारत के प्रत्येक नागरिक की इच्छा होती है भारत में चारों फ्राम तीर्थ करना। खासकर बुजुर्गों की तो होती ही है। मनुष्य के स्वभाव को, उसके वृद्धावस्था के मनोभाव को मफ्रयप्रदेश सरकार ने समझा है। हर भारतीय परिवार का और खासकर बुजुर्गों की अंतिम इच्छा रहती है कि या तो वे स्वयं या उनके बेटा–बेटी, उन्हें तीर्थाटन करवा दें। पर आर्थिक अभाव में यह सपना सभी बुजुर्गों का पूरा नहीं हो पाता। मफ्रयप्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह योजना बनाकर भारतीय परिवार परंपरा को और भारत की मूल संस्कृति को जिस तरह से मजबूत करने का प्रयास किया है, वह सराहनीय है। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का अभिनंदन करते हैं। सच में, यह मानवीय निर्णय प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में सराही जाएगी।

ऐसा ही एक निर्णय उन्होंने ''बेटी बचाओ अभियान'' के तहत लिया है। यह निर्णय भी सराहनीय ही नहीं, मील का पत्थर साबित होगा। मफ्रयप्रदेश की भाजपा सरकार ने तय किया है कि यदि किसी दंपती के दो बेटियां हैं और उनकी उम्र 55 वर्ष हो चुकी है, तो उन्हें मफ्रयप्रदेश सरकार एक हजार रुपये का पेंशन देगी।

श्री शिवराज सिंह ने कहा कि मफ्रयप्रदेश सरकार परिवारभाव से चल रही है और आगे भी परिवारभाव से चलेगी। सरकार यदि परिवार की भूमिका में आ जाए तो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने प्रदेश का मुखिया हो जाता है। मफ्रयप्रदेश सरकार के इस दो निर्णयों से प्रदेश की सवा सात करोड़ जनता की बांछे खिल गई हैं। गांव–गांव में, चौपाल–चौपाल पर भाजपा की प्रशंसा हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मफ्रयप्रदेश को ''बाल दय रोग'' से मुक्त करना चाहते हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश को यह विश्वास दिलाया है कि कोई भी बालक यदि दय रोग से पीड़ित है तो उसे तत्काल मफ्रयप्रदेश के चार चिन्हित अस्पतालों में से एक में भर्ती कराएं। मफ्रय प्रदेश की सरकार इसका खर्च उठायेगी। मफ्रय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सामाजिक सुरक्षा के प्रमुख 'स्तंभ' बनकर उभरे हैं। मफ्रय प्रदेश की जनता अपनी आंखों से भारतीय जनता पार्टी के दर्शनशास्त्री एवं पुरखे पं. दीनदयाल उपाफ्रयाय द्वारा प्रस्तुत 'अंत्योदय' विचारफ्रारा को जमीन पर साकार होते देख रही है।

संसद में बहस : आम बजट 2012&13

गत 16 मार्च 2012 को केंद्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में आम बजट प्रस्तुत किया। संसद के दोनों सदनों में इस पर चर्चा हुई। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने चर्चा में भाग लेते हुए तर्कों एवं तथ्यों के साथ बजट की जमकर आलोचना की। भाजपा सांसदों ने कहा कि यह दिशाहीन, निराशाजनक और महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। इसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। इसमें विकास के लिए कोई दूरदृष्टि नहीं है। इस बजट से केंद्र सरकार का गरीब और कमजोर वर्ग विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया है। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर में वृद्धि के चलते बजट से सिर्फ महंगाई बढ़ेगी। बजट पर विस्तार से जानकारी के लिए हम यहां राज्यसभा में विपक्ष के नेता सर्वश्री अरुण जेटली, पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री जसवंत सिंह एवं यशवंत सिन्हा, प्रभात झा एवं पीयूष गोयल द्वारा दिए गए भाषणों के संपादित पाठ प्रकाशित कर रहे हैं।

बजट प्रावधानों से बढ़ेगी महंगाई : अरुण जेटली

गत 26 मार्च 2012 को राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने आम बजट की कड़ी आलोचना करते हुए उसके श्वफ्रानों की फ्राज्जियां उड़ाइ। श्री जेटली ने कहा कि यह बजट 1991 के पहले वाली मनोदशा से बनाया गया है। बजट में आम लोगों को राहत देने की बजाय करों का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिससे महंगाई के बढ़ने की आशंका है। हम यहां श्री जेटली द्वारा अंग्रेजी में दिए गए भाषण का हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत कर रहे हैं :

Jh मान उपाध्यक्ष महोदय, लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गये सामान्य बजट और वित्त विधेयक ने देश की आर्थिक भावनाओं को ठेस पहुंचायी है। हमारी अर्थव्यवस्था उस चरण से गुजर रही है कि अर्थव्यवस्था से संबंधित भावनाओं को प्रोत्साहन की जरूरत है। लेकिन इस बजट ने इसके ठीक विपरीत किया है। महाशय, जब मैं अपने देश की अर्थव्यवस्था और नीति के संबंध में हमारे वृहत् दृष्टिकोण की ओर देखता हूं तो एकबारगी तो उस विचार का भी ध्यान आता है जिसने हमारे अधिकांश आर्थिक निर्णयों को लंबे समय तक प्रभावित किया। वास्तव में, 1991 का वर्ष वह निर्णायक बिंदु है जिसके बाद सरकारें चाहे वह श्री नरसिंहा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रही हो या संयुक्त मोर्चा की सरकार या एनडीए सरकार, सबका दृष्टिकोण पूर्णतः बदल गया। उसके बाद से अलग–अलग सरकारें आईं पर उन सब की नीति संबंधी दिशा बहुत कुछ एक जैसी रही, और इस रूप में अर्थव्यवस्था को अधिक सकारात्मक रूप में देखा गया। महाशय, बजट का अर्थ एकमात्र एक लेखा कागजात के रूप में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसमें एक सुनिश्चित नीति संबंधी दिशा होनी चाहिए। महोदय, दुर्भाग्यवश 2012–13 का बजट एक ऐसा बजट है जिसे 1991 से पूर्व की मानसिकता से तैयार किया गया है। मैंने 1991 को एक निर्णायक मोड़ कहा है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे जिन्होंने तब एक भाषण दिया था जो कि बजट प्रस्तुत करने के समय दिये जाने वाले भाषणों में मील का पत्थर माना जाता है। डॉ. सिंह ने 1991 के भाषण के पैरा 106 में जो कहा था वह मैं उद्धरण रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं: '' हमने देखा है कि हाल के वर्षों में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अप्रत्यक्ष करों पर निर्भरता अत्यधिक बढ़ती जा रही है। इससे लागत, ईंधन के मूल्य, मुद्रा–स्फिति में वृद्धि होती है और इसका प्रभाव प्रतिगामी है। इसलिए संसाधन जुटाने के प्रमुख स्रोत के रूप में मैं इनपर निर्भरता को सही नहीं मानता हूं। वास्तव में,

सीमा–शुल्क और उत्पाद–शुल्क लेवी के लिए सभी प्रस्तावों का प्रभाव केंद्र सरकार के संदर्भ में राजस्व की दृष्टि से नकारात्मक है।'' महाशय, अधिक कर, सुस्त अर्थव्यवस्था, कम वृद्धि–दर ने 1991 से पूर्व आर्थिक गतिविधियों को कम कर दिया था और आपने अधिक करों को अस्वीकृत कर व्यय को संतुलित किया। और हम तब से पिछले दो दशकों के दौरान सतत् रूप से तर्कसंगतिकरण की प्रक्रिया घटते हुए देख रहे हैं। तर्कसंगतिकरण का बड़ा भाग वह था कि आपको एक ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए जो बहुत अधिक प्रभावशाली, बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी हो जहां आपको कर न बढ़ाना पड़े बल्कि आप आर्थिक गतिविधियों का आधार और वॉल्यूम बढ़ा सकें।

आम आदमी पर करों का बोझ लादा

आर्थिक गतिविधियों का आधार और वॉल्यूम बढ़ाने से टैक्स का आधार बढ़ता है, और इससे अर्थव्यवस्था के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी कर संरचना और प्रोत्साहक वातावरण सृजित कर वित्त मंत्री अधिक राजस्व एकत्र कर सकेंगे और संतुलित बजट बना सकेंगे। हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में दृष्टिकोण धीरे–धीरे बदला है, पर इस बजट में जो पुराना दृष्टिकोण उभरकर आया वह यह है कि 'जहां भी टैक्स लगाया जा सके, लगा डालो।' यह गैर प्रगतिशील दृष्टिकोण 1991 के बाद के युग में पहली बार लौट कर आ रहा है। हम करारोपण की वर्तमान संरचना में जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं उस पर एक दृष्टि डालने का प्रयास करते हैं। लोग या तो अधिक आय समूह वाले हो सकते हैं या कम आय समूह वाले; और इसमें सभी आम–आदमी शामिल हैं। आपने यह निर्णय लिया है – और प्रत्येक समाज यह निर्णय लेता है – कि उन पर कर लगाया जाए जो आय सृजित करते हैं। इसलिए आपने लोगों की आय पर कर लगाया। अब आपने उन पर कर लगाने का निर्णय लिया है जो लोग व्यय करते हैं। अगर आपकी नजर हममें से किसी पर भी पड़ती है, आप संबंधित वस्तु का उत्पाद शुल्क बढ़ा देते हैं। इसलिए, उत्पाद शुल्क बढ़ जाता है। चीनी 'सामान प्रतियोगिता' में बहुत सस्ती पड़ने लगती है। इसलिए, अंतराष्ट्रीय बाजार की बात तो छोड़ ही दें, घरेलू बाजार में भी उपभोक्ता वही सामान खरीदते हैं जो सस्ता पड़ता है। जबकि आप अपने सामान को मंहगा बनाते जा रहे हैं। आप मुझ पर उस समय कर लगाते हैं जब मैं कमाता हूं, उस समय कर लगाते हैं जब मैं कुछ उत्पादित करता हूं, उस समय कर लगाते हैं जब मैं व्यय करता हूं। फिर, अनेक प्रकार के केन्द्रीय और राज्य कर होते हैं, चाहे यह वैट हो या टैक्स का कोई अन्य रूप हो। अगर वस्तु या सामान का कोई घटक बाहर से मंगाया जाता है तो उस पर भी कर लगता है। ठीक है कि इस पर कर लगना चाहिए। अगर यह नगर या राज्य से बाहर से आ रहा है तो इसपर प्रवेश शुल्क होगा। अब आपने सभी प्रकार की सेवाओं पर कर लगाने का निर्णय लिया है। एक नकारात्मक सूची भी है जिससे बहुत अधिक स्फीतिकारी असर पड़ने का खतरा है। हम सब को अनेक प्रकार के सेवाओं की जरूरत पड़ती है। इसलिए, नकारात्मक सूची की 17 वस्तुओं को छोड़कर सभी पर कर है। महाशय, मैं सुबह की सैर करने वालों में से हूं। बहुत सुबह लोदी गार्डन जाता हूं। वहां एक सुलभ शौचालय है। 1 अप्रैल से, जितनी बार हम उसमें जाएंगे, हमें टैक्स देना पड़ेगा। आपने अब जो कर लगाया है उसका दायरा यह है कि ऐसी सेवाएं भी आपकी 'छूट सूची' में नहीं है। 'छूट सूची' की सेवाओं को छोड़कर जीवन की सभी प्रकार की गतिविधियों पर टैक्स है– उस पानी पर, जो मैं पीता हूं, उस बिजली पर जिसका उपभोग मैं करता हूं, उस सड़क पर जिसपर मैं चलता हूं, उस घर पर जिसमें मैं रहता हूं, उस संपत्ति पर जो मैं खरीदता हूं, और उस बचत पर जो मैं करता हूं। इसका मतलब यह है कि भारत में हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया है जहां मेरे द्वारा किए जाने वाले किसी भी संभावित काम पर 'टैक्समैन' कर लगाता है, जिससे हमारा समाज फिर से सबसे बड़े कर–समाजों में से एक हो जाता है। इसलिए, वह 'समस्त तर्कसंगतिकरण' 1991 के बाद से हमने जिसे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपनाया हुआ है ऐसा प्रतीत होता है कि उसे वापसी का रास्ता दिखाया जा रहा है। अगर आप किसी कागज के टुकड़े पर या लिफाफे के पीछे जोड़ना शुरू कर दे तो आप पाएंगे– वित्त मंत्री साहब जिनके पास राजस्व विभाग का पूरा महकमा है, इस बात को बेहतर समझेंगे–कि मात्र 30 प्रतिशत कर या 2 प्रतिशत शिक्षा उपकर ही नहीं है जो आपको देना पड़ता है। एक कमाने वाले व्यक्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर का पूरा बोझ उसकी कमाई के 50–60 प्रतिशत के बीच होता है। एक आम आदमी के लिए जो इतना तो नहीं कमा रहा कि उसे आयकर देनी पड़े पर जिन सेवाओं का वह उपभोग करता है जैसे मकान, परिवहन, आदि वह भी आपके नए युग के करों के बोझ तले दबा है।

अर्थव्यवस्था दिशाहीन

महोदय, इसका क्या कारण है कि हम यहां पहुंच गए हैं? महोदय, जब यूपीए–प्रथम बना था और यह मैंने सभा में पहले भी कहा है– हम एक आलोचना या टिप्पणी अक्सर किया करते थे कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में शक्ति के दो केन्द्र नहीं हो सकते। उस समय आपने सोचा कि

यह एक राजनीतिक आलोचना थी। मैं यह अवश्य कहूंगा कि यूपीए–1 में आपके वामदलों के साथ विचारधारा संबंधी मतभेद थे, परंतु कम से कम ऐसा तो होता कि आपके अपने गठबंधन के भीतर दो शक्ति केन्द्रों के बीच हम कोई समन्वय देख पाते। लोकतंत्र में सामान्यतया प्रधानमंत्री देश के स्वाभाविक नेता होते हैं, वह जवाबदेह होते हैं और अंतिम कहना उन्हीं का होना चाहिए। पर आपके यहां एक समानांतर संरचना तैयार हो गई जिसने सरकार को परामर्श देना प्रारंभ कर दिया। यह संरचना सरकार से बाहर थी। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं बनाने का निर्णय लिया। उनमें से कुछ अच्छी हो सकती हैं, उनमें से कुछ अच्छी नहीं भी हो सकती हैं। परन्तु उन सबके पास एक बिल था जिसे किसी को चुकाना था। आज आप उस स्थिति में हैं जहां हमें बहुत भरोसा नहीं है कि दो शक्ति केन्द्र विचारधारा की दृष्टि से एक समान धरातल पर हैं। अब, सरकार में कुछ अत्यंत अनुभवी लोग हैं जो 91 के बाद के युग में हुए बदलावों के अग्रदूत रहे हैं, पर ऐसा जान पड़ता है कि एक अन्य वैकल्पिक शक्ति केन्द्र भी है जो यह सोचता है कि वोट के लिए 91 से पूर्व की स्थिति में जाना आवश्यक है। अब हम इस स्थिति से गुजर रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि आर्थिक नीति और नियोजन के क्षेत्र में वित्त मंत्री और नॉर्थ ब्लॉक पर बजट में संतुलन बिठाने की जिम्मेदारी होती है। इसलिए उन्हें हम पर कर लगाना पड़ता है। और यह उनकी जिम्मेदारी होती है कि अंततः बजट किस प्रकार संतुलित बने। इसका व्यय कहां पर किया जाना है यह निर्णय कहीं और किया जाता है। और, इसलिए सरकार के बाहर बनाए जाने वाले सभी कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए जो सरकार अपनाती है, हम ऐसी स्थिति देखते हैं कि एक कार्यालय यह निर्णय लेता है कि कहां कर लगाना है जबकि दूसरी संस्था यह निर्णय लेती है कि इसका व्यय कहां करना है। यही कारण है कि हमारी अर्थव्यवस्था उस दिशा में जा रही है जो, कम शब्दों में कहा जाए, तो चिंताजनक है।

यूपीए को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत

महोदय, हम जिस समस्या का सामना कर रहे हैं उसका आत्मनिरीक्षण अवश्य करना चाहिए। एक बात जो माननीय वित्त मंत्री नियमित रूप से दोहराते हैं– इस मत के समर्थन में व्यापक जनमत है और मेरा भी यही मत है कि हमारे बीच काफी राजनैतिक मतभेद हो सकते हैं, किन्तु देश की खातिर परस्पर समर्थन की आवश्यकता है, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन का आधार 'सहयोगात्मक संघवाद' है। यही वाक्यांश वह प्रयोग करते हैं और उन्हें विपक्ष सहित समाज के विभिन्न वर्गों से समर्थन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का प्रबंधन विशेषकर विभाजित राजव्यवस्था की स्थिति में नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों है कि हम उस अवस्था में पहुंच गए हैं जहां आर्थिक नीति के लिए जैसे समर्थन की आवश्यकता होती है, वह नहीं मिलती है? विचारों की जानकारी है, रोडमैप की जानकारी है, कुछ मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, परन्तु कई मुद्दों पर काफी सहमति भी हो सकती है। मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से आत्मनिरीक्षण करना है कि वह सर्वसम्मति बनाने में विफल क्यों हैं जिसकी आवश्यकता है और इसमें से काफी कुछ सरकार के अपने दृष्टिकोण से उत्पन्न होता है जो कि एक राजनैतिक दृष्टिकोण है। मैंने यह पहले कहा है। आप इस सभा के हर हिस्से को देख सकते हैं। यूपीए–1 में वामदलों ने साढ़े चार सालों तक सरकार को समर्थन दिया। और एक दिन अचानक उन्होंने निर्णय ले लिया कि क्योंकि उन्होंने किसी और का प्रबंध कर लिया, उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं रही। वामदलों ने अपने आपको अपमानित महसूस किया और उन्होंने उनका विश्वास खो दिया। अब, यहां पर दो समूह हैं। मैं किसी के बारे में कुछ भी अनादरपूर्ण नहीं कहना चाहता हूं, परन्तु आपने उत्तर प्रदेश की दो मुख्य पार्टियों बसपा और सपा के समर्थन का प्रबंध कैसे किया? पांच सालों से या आठ सालों से उनके राष्ट्रीय नेताओं पर मुकदमे लटकते रहे और फिर भी वे उत्तर प्रदेश की इन दोनों पार्टियों से समर्थन पा सके। उत्तर प्रदेश में चुनावों ने दर्शाया है कि परिवारों का करिश्मा अब लुप्त हो रहा है और वह अब उन्हें मत नहीं दिला सकता। इसलिए, उन्हें उत्तर प्रदेश से, जहां तक इन दो पार्टियों का संबंध है, राजनैतिक समर्थन प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सहायता की आवश्यकता पड़ी। क्या आर्थिक मुद्दों पर आप कभी भी एक राजनैतिक सर्वसम्मति बना पाएंगे?

महोदय, अपने सहयोगी दलों की ओर देखिए। ये हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े हुए हैं।

तमिलनाडु से आपके सहयोगी का कहना है, ''आपके एक मंत्री और द्रमुक के बीच सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता है।'' द्रमुक और कांग्रेस का एक मंत्री। एक जेल में है और दूसरा सत्ता में है। आपने क्या किया? हम इसका विश्लेषण करते हैं। आपमें इतनी अनिश्चितता क्यों है कि आपके पश्चिमी बंगाल के सहयोग की क्या प्रतिक्रिया होगी? कड़वी सच्चाई यह है कि रेलवे बजट के मामले में आप तृणमूल कांग्रेस से संबंधित एक कमजोर मंत्री का लगाव पा गए। वह एक साक्षात्कार में कहते हैं कि प्रधानमंत्री और सरकार मेरे समक्ष खड़ी रहती, तृणमूल कांग्रेस नहीं। संभवतः आप इसमें विभाजन चाहते थे। और इसलिए अब वे विचार

कर रहे हैं, ''क्या यह एक प्रकार का गठबंधन है, जिसमें हम शामिल हैं?'' यदि ऐसे मुद्दों को जिन्हें आप सर्वसम्मति से सुलझा सकते हैं, दांव–पेंच से निपटाए जा रहे हैं, तो आर्थिक नीतियों में सर्वसम्मति कैसे संभव होगी। विपक्षी राज्यों के मुख्य मंत्री शिकायत कर रहे हैं कि राज्यपाल विधानों के लिए महीनों और सालों तक सहमति देने के लिए राजी नहीं हो रहे, चुने हुए मुख्यमंत्री की उपेक्षा कर लोकायुक्तों की नियुक्ति की जा रही है; सीबीआई का उन राज्यों के विरुद्ध दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकारी योजनाओं के मामलों में और यहां तक कि अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में, वे एक प्रकार का भेदभाव बरतते हैं। वित्त मंत्री जी के सबसे पसंदीदा कार्यक्रमों में से एक वस्तु एवं सेवा कर में, हममें से बहुत लोग अच्छाई देख सकते हैं। परंतु मैं आपको बता सकता हूं कि व्यापक सहमति बना पाने में आपकी अक्षमता किसी अन्य कारकों से अधिक इस सरकार के राजनैतिक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है।

महोदय, आर्थिक नीति की सर्वसम्मति राजनैतिक वातावरण से मूलभूत तरीके से संबद्ध है। यह एक कठोर सच्चाई है और सरकार को इसे महसूस करना चाहिए। राजनीति में कुछ क्षेत्र हैं जहां हम असहमत होंगे। परंतु यदि राजनीति में भद्रता है तो उन असहमतियों के बावजूद देश की खातिर हम साथ आ सकते हैं और हम कई क्षेत्रों में साथ आते भी हैं। परन्तु यदि राजनीति प्रतिशोध की है। यदि राजनीति सबक सिखाने की है और यदि राजनीति दांव–पेंच की है, तो आपमें सर्वसम्मति बनाने की काबिलियत कभी नहीं आ पाएगी। और मुझे लगता है यह एक कठोर सच्चाई है जिसे सरकार को अवश्य महसूस करनी चाहिए। महोदय, यह कहने के पश्चात् मैं अर्थव्यवस्था के कुछ कठोर तथ्यों पर आता हूं, जहां तक इस बजट का संबंध है। क्या यह बजट अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को ईमानदारी से परिलक्षित करता है?

राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी

वित्त मंत्री ने कहा है इस वर्ष राजकोषीय घाटा 5.9 प्रतिशत के डरावने स्तर पर है, मुझे लगता है कि यह 5. 9 प्रतिशत देखने में अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए लिखा गया है, क्योंकि 6 प्रतिशत से अधिक कुछ भी से और अधिक भय उत्पन्न होता। यह उन पुराने बाटा के जूतों जैसा है जो हमेशा ही कुछ रुपये 95 पैसों की कीमत पर बेचे जाते थे, ताकि वे ऊंची कीमत के न जान पड़ें। यदि कुछ गैर–व्यवस्था और कुछ अधिक सब्सिडी (राजसहायता) पर गौर किया जाए, तो मुझे डर है कि यह बढ़ सकती है। किंतु मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा डर सही न हो। अगले वर्ष के लिए क्या अनुमान लगाया गया है, उस पर आते हैं। अगले वर्ष के लिए यह अनुमान लगाया गया है कि हमारा राजकोषीय घाटा 5.1 प्रतिशत होगा। अब किसी भी बजट में सबसे डरावनी संख्या यह राजकोषीय घाटा होती है। इस तरह 5.9 प्रतिशत से 5.1 प्रतिशत हो जाएगा। अब यह किस बुनियाद पर रखा हुआ है? मैंने इस बजट में कर राजस्व देखे हैं, कारपोरेट कर, आय पर कर, संपदा कर, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और संघ राज्य क्षेत्रों पर कर। इस प्रकार, आपने बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। मैंने वास्तव में इसका योग किया है कि कितनी वृद्धि होने वाली है। आपने अनुमान लगाया है कि वृद्धि 1.73 लाख करोड़ की होगी। अब, मुझे यह नहीं मालूम है यदि अर्थव्यवस्था अगले वर्ष 12 प्रतिशत की दर से वृद्धि करने वाली है कि हमारा राजस्व इतनी बड़ी संख्या में बढ़ने वाला है। किन्तु, एक क्षण के लिए इस प्रत्याशित वृद्धि को किनारे कर देते हैं। आपका बजट भाषण पृष्ठ–5, अनुच्छेद–22 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का हवाला देते हुए कहता है, सभी आवश्यक खर्च उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए यदि अगले वर्ष उम्मीद करते हुए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हो जाता है तो इसका समस्त भार उपलब्ध कराया जाएगा। अब यदि आप यह उपलब्ध कराते हैं, तो फिर व्यय का अनुमान आप कैसे लगाते हैं? क्या इसमें वृद्धि होगी? क्या इसमें गिरावट आएगी?

महोदय, पिछले वर्ष सब्सिडी पर व्यय की गई कुल राशि के संबंध में – मैं खाद्य सब्सिडी, पेट्रोल सब्सिडी और उर्वरक सब्सिडी को लेता हूं – आपने लगभग 1,43,000 करोड़ का अनुमान लगाया था। आपने खर्च किए 2,16,000करोड़। इस तरह यह लगभग 70000 करोड़ अधिक है। अगले वर्ष आप उम्मीद करते हैं, एक बार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू हो जाने पर यह संख्या 26,000 करोड़ कम होकर 1,90,000 करोड़ पहुंच जाएगी। इस प्रकार, कैसे यह संख्या कम होती है मुझे समझ नहीं आता है। मैंने आपके व्यय बजट के विवरणों को देखा। जब मैंने व्यय बजट के पृष्ठ संख्या 30 पर उर्वरक सब्सिडी को देखा, जबकि अंतरराष्ट्रीय कीमतें ऊपर जाने वाली हैं, आपको लगता है कि यह 68,225 करोड़ से 61,000 करोड़ तक नीचे आ जाएगी।

जहां तक खाद्य सब्सिडी का संबंध है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कारण मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखने के बजाय आप समझते हैं कि इन सभी की व्यवस्था 72,000 करोड़ रु. से हो जाएगी। यदि 75,000 करोड़ रु. का प्रावधान हो जाए तो सभी चीजों का ख्याल रखा जा सकेगा। और साथ ही पिछले

वर्ष के मामले में तेल कंपनियों को मुआवजे के लिए 20,000 करोड़ रु. का पूर्वानुमान किया गया था। आपने इसके लिए 65,000 करोड़ रु. का भुगतान किया। अगले वर्ष इस बात का पहले से ही अनुमान होते हुए भी कि तेल का मूल्य अपने मौजूदा 125 डालर के स्तर से बढ़ने जा रहा है, आपको यह सोचना आश्चर्यजनक है कि इस वर्ष 65,000 करोड़ रु. के बजाय 40,000 करोड़ रु. ही पर्याप्त होगा। इसलिए आप कराधान में वृद्धि दिखाते हैं। आप यह दिखाते हैं कि सब्सिडी कम हो जाएगी। और इन सभी का निवल प्रभाव यह होने जा रहा है कि यह 5.9 प्रतिशत 5.1 प्रतिशत हो जाएगा। और आशा है कि जब अगले वर्ष आंकड़े तैयार किए जाएंगे तो आप पाएंगे कि यह आंकड़ा भी गलत साबित हो गया है। आप इन सभी घाटों का किस प्रकार वित्तपोषण कर रहे हैं? मैं सोचता हूं कि शायद यह अल्पकालिक ऋणों, भारतीय रिजर्व बैंक और बाजार के जरिए हो रहा है। पिछले वर्ष आपका नकद प्रबंधन बिल 20,000 करोड़ रुपए होने की आशा थी। आपने 93,000 करोड़ रु. खर्च किए। फिर, भारतीय रिजर्व बैंक से 95,000 करोड़ रु. होने जा रहा है।

उल्टी दिशा में जा रही पूंजी

अर्थोपाय अग्रिम– बाजार जो एक लाख चार हजार करोड़ रु. होने का पूर्वानुमान था, सात लाख करोड़ रु. होने जा रहा है जो आप बाजार से जुटाएंगे। महोदय, जहां तक सार्वजनिक वित्त का संबंध है, यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आपने इसे कर बढ़ाकर पूरा करने का प्रयास किया है। अब हम यह देखें कि इन सभी का क्या प्रभाव होने जा रहा है, सभी क्षेत्रों में उत्पाद शुल्क दो प्रतिशत बढ़ गया है। सेवा कर का कवरेज बढ़ गया है। सेवा कर की दर जो 14 प्रतिशत थी और जिसे घटाकर 8 प्रतिशत किया गया था, इसे धीरे–धीरे बढ़ाकर आठ प्रतिशत से 10 प्रतिशत और अब 12 प्रतिशत कर दिया गया है। स्वर्णकारों और जौहरी का पूरा उद्योग हड़ताल पर सड़क पर है, क्योंकि विनिर्माण एवं निर्यात ठप्प हो गया है। महोदय, इस बारे में वित्त मंत्री की नीति क्या होनी चाहिए? उनकी नीति यह होनी चाहिए कि किस प्रकार अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी कंपनियों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जाए, किस प्रकार उनको और अधिक लाभकारी बनाया जाए, किस प्रकार उनको और अधिक सक्षम, कम निष्क्रिय किया जाए, और किस प्रकार एक ऐसा माहौल बनाए जाए, जिसमें लोग भारत में निवेश करना चाहेंगे।

पिछले वर्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) में गिरावट आई है। इस वर्ष इसमें मामूली बढ़ोतरी हुई है और यह वृद्धि इस कारण से नहीं हुई है कि उद्योग एवं परियोजनाओं के लिए वास्तविक निवेश हो रहे हैं, बल्कि इसलिए कि कुछ प्रबंधनों में बदलाव हुए हैं। और इसलिए जब मौजूदा कंपनियों या तेल ब्लाकों के प्रबंधन बदलते हैं तो वास्तव में काफी निधियां देश में आती हैं। इनसे हमें अतिरिक्त रोजगार पैदा करने में मदद नहीं मिल रही है क्योंकि उद्योग तो पहले से हैं ही। पिछले वर्ष अत्यधिक मुद्रास्फीति थी और यह बजट मुद्रास्फीति और अधिक बढ़ा सकता है। आपका बजट मीडिया एवं जनता की नजर में 'अशक्त नीति' है। आपके अवसंरचना क्षेत्र में मंदी है और मैं आपको यह आंकड़ा दिखा दूंगा कि हम अवसंरचना क्षेत्र में कहां खड़े हैं। आपकी ब्याज दरें अधिक हैं। पूंजीगत लागत बढ़ गई है और इसलिए ऋण लेना महंगा हो गया है। यह न केवल उद्योग को बल्कि आम आदमी को प्रभावित करता है। इसलिए छोटे ऋण लेकर गाड़ी या जेवर खरीदने की महती इच्छा का क्या होगा? संपूर्ण हाउसिंग या रियल सेक्टर क्षेत्र, जो सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है, इससे प्रभावित हुआ है। आपकी ईएमआई बढ़ गई है। वे राजनैतिक स्थिरता के बारे में भी बहुत आश्वस्त नहीं हैं। आपका कराधान अधिक है और भूतलक्षी कराधान भी है। अब इन सभी वृद्धियों को लेकर भी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आप उत्साहित हैं। महोदय, वर्ष 1991 से लेकर आज तक या कुछेक, एक या दो वर्ष पूर्व जब कभी कोई, सरकार से या विपक्ष से, बाहर जाता था तो भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर को सर्वाधिक आकर्षक निवेश लक्ष्य के रूप में दिखाता था। आज निवेश करने के इच्छुक लोगों को तो भूल ही जाएं, उल्टे यहां से पूंजी बाहर जा रही है। हमारे उद्योगपति जो अधिग्रहण कर रहे हैं, उसका कारण यह नहीं है कि वे बहुत बड़े हो गए हैं और वे विश्व के किसी भी हिस्से में कंपनियां खरीद सकते हैं, बल्कि कारण यह है कि वे महसूस करते हैं कि भारत अब व्यवसाय करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं रह गया है।

और इसलिए पूंजी उल्टी दिशा में जानी शुरू हुई और यह अभी भी जारी है। इस वातावरण को सही करने की जरूरत थी और मुझे अफसोस है कि महोदय, यह बजट इस वातावरण को सही करने में सफल नहीं रहा है। मैंने अवसंरचना के बारे में उल्लेख किया था। मैं आंकड़े देख रहा था। 'राजमार्ग' के बारे में कितनी बार इस सदन को कहा गया है कि इस परियोजना को तब शुरू किया जा सकता था, जब एनडीए शासन में था, अब प्रतिदिन 20 किमी का निर्माण किया जा रहा है। आईए आंकड़े लेते हैं। वर्ष 2010–11 में 2500 किमी के लक्ष्य के मुकाबले 1780 किमी का निर्माण हुआ और यदि इसे 365 दिन में विभाजित किया जाए तो यह प्रति दिन पांच किमी से भी कम बैठता है। इस वर्ष के आंकड़े ज्ञात नहीं हैं, किंतु लक्ष्य के कम होने

की संभावना है।

दी गई संविदाओं की संख्या इतनी कम है कि इसका प्रभाव अगले वर्ष में परियोजनाओं पर पड़ेगा। जहां तक इस बीच आपके हवाई अड्डों का संबंध है, हवाई अड्डों के निर्माण में तेजी आई और फिर अचानक इसमें कमी आ गई है। आपके पोत पत्तन की योजना बनाई गई है। इसलिए जहां अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है और पोत पत्तनों में भीड़–भाड़ हो तो आपको विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप का प्रयोग करना होता है क्योंकि कुछ सर्वोत्तम अवसंरचना हेतु एक अतिरिक्त पोत पत्तन की योजना बनाई गई है। ऊर्जा क्षेत्र में, मुझे खुशी है कि शिंदे जी यहां हैं, हमने सुधार किया है, और अधिक सुधार करने की जरूरत है। किंतु यदि कोयले खंडों में इसी प्रकार की स्थिति बनी रही तो ऊर्जा मंत्री का उत्साह भी कम हो जाएगा। जिस तरीके से कोयला खंड आबंटित किए गए हैं, जिस प्रकार बड़ी संख्या में परियोजनाओं के सामने कोयले की अपर्याप्तता की समस्या है, लोग उन परियोजनाओं को छोड़ने वाले हैं। ऐसी स्थिति में हमारी उन परियोजनाओं का क्या होगा? और चूंकि मैं इस विषय पर यहां हूं, महोदय, मेरा यह सोचना है कि किसी न किसी समय जब समय मिले तो सरकार को सहमत होना चाहिए– उच्चतम न्यायालय ने इस बारे में एक दृष्टिकोण दिया है कि किस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का वितरण या आबंटन किया जाए– हमें इस सदन में व्यापक बहस की जरूरत है। 2जी से लेकर कोयले के खंडों तक, हमें इस बारे में विचार करने की जरूरत है कि प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के संबंध में देश की नीति कैसी होनी चाहिए ताकि हमारी नीति पादरर्शी हो सके।

गरीबी की चुनौती

हमारे पास पूर्व निर्धारित मूल्य पर कम से कम वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए प्राकृतिक संसाधन तो उपलब्ध हैं ही चाहे वे बाजार द्वारा हों या इंडेक्शेसन द्वारा। मैं समझता हूं कि इसके लिए व्यापक बहस की जरूरत है जो इस सदन में अब तक नहीं हुआ है। महोदय हमने हाल ही में गरीबी रेखा को देखा, और यह बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि वर्ष 2004–05 और वर्ष 2009–10 के बीच 5 वर्षों में गरीबी के आंकड़ों में 7.3 प्रतिशत की कमी आई है। योजना आयोग तेंदुलकर समिति गठित करने को स्वीकृति देता नजर आ रहा है। तब रिपोर्टें आई हैं कि यह उस लक्ष्य को बदलने पर आधारित है जिसमें एक व्यक्ति को गरीबी रेखा से बाहर करने के लिए 32 रु. को पर्याप्त माना गया था। अब यह घटकर 28 रु. हो गया है। और अब यह प्रतीत होता है, महोदय, कि 7.3 प्रतिशत के आंकड़े का हिसाब लगाते समय वित्त मंत्री इस प्रश्न में उलझेंगे कि इस कमी को निर्धारित करने के लिए दोपहर भोजन योजना जैसी स्कीमों को ध्यान में लिया गया है जो कि गरीबी दूर करने के लिए विदेशी सहायता है। इसलिए ये ऐसे लोग हैं जिनको स्वयं के खाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, वे अभी भी गरीब हैं किंतु ऐसी स्कीमों, ऐसी विदेशी सहायता के कारण यदि उनको खाने के लिए पर्याप्त पैसे हैं तो मैं निश्चित नहीं कह सकता कि यह सही आकलन है या नहीं। यदि मेरा मानना सही नहीं हो तो मैं अपने विचार को सही कर लूंगा।

भंडारण सुविधा का अभाव

महोदय, कृषि क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियां हैं। खेती योग्य भूमि कम हो रही है। जनसंख्या बढ़ रही है। सौभाग्यवश, इस वर्ष हमारी फसल अच्छी रही किंतु फिर इनपुट लागत काफी बढ़ गई है। अब विद्युत लागत बढ़ गई है, उर्वरक लागत भी बढ़ी है, बीज की लागत में बढ़ोतरी हुई है। आज आपके सामने कई प्रकार की समस्याएं हैं। जब आपको कमी थी तो आपको कमी की समस्या थी। मैं आर्थिक सर्वेक्षण में की गई टिप्पणियों को देख रहा था। यदि हम पृष्ठ 181 से आगे देखें तो इसमें 'कृषि' का उल्लेख है। पृष्ठ 184 में लोगों की बदलती खाद्य आदतों के बारे में उल्लेख किया गया है। इसलिए जब हम न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते हैं तो हमें उसे ध्यान में रखना होता है ताकि किसान लोगों की बदलती खाद्य आदतों के कारण वैकल्पिक दिशा में जाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। उसके बाद इसमें ऊर्जा की उपलब्धता एवं लागत दोनों के बारे में उल्लेख है। इसमें पृष्ठ 197 में खरीद का माह–बार ब्यौरा दिया गया है। और चूंकि हमारी फसल बहुत अच्छी रही इसलिए हमें अब अधिक समस्याएं हैं। प्रायः विभिन्न अवधियों में हमारे पास आवश्यक बफर स्टाक की मात्रा से डेढ़ से दो गुना या इससे अधिक मात्रा है और इसलिए आपको अन्न के सड़ने की समस्या है क्योंकि पर्याप्त भंडारण सुविधाएं स्थापित नहीं की गई हैं। ये सभी क्षेत्र चिंता के विषय हैं। अब बजट में आपका प्रस्ताव है जहां फसल बीमा के निमित्त राशि वास्तव में कम हो गई है।

मनरेगा में खामियां

महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसी योजनाएं कितनी भी व उपयोगी एवं पवित्र रही हों मेरे विचार से इस पर भी समय समय पर दोबारा विचार किए जाने की आवश्यकता है। इस वर्ष आपने आबंटन को 40,000 करोड़ रु. से घटाकर 33,000 करोड़ रु. कर दिया है। अर्थात् 700 करोड रु. कम किया गया है। यह रोजगार देने वाली योजना है। यह जीविकोपार्जन योजना है। किंतु

यह आवश्यक है कि जीविकोपार्जन योजना को कभी भी परिसंपत्ति अर्जित करने वाली योजना नहीं होनी चाहिए। दोनों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। किसी न किसी प्रकार हम उस आधार की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं कि चूंकि यह जीविकोपार्जन योजना है इसे परिसंपत्ति सृजन योजना नहीं होनी चाहिए। आपको अनिश्चित काल के लिए ऐसी योजना नहीं हो सकती जहां आप गढ्डे खोद लें और फिर उनको भर दें और कहें कि आपने नौकरियां पैदा की हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय योजना को जारी रखने और विभिन्न प्रकार के अवसंरचनात्मक क्रियाकलापों से इसको जोड़ने से हमें कौन रोकता है? एक क्षेत्र है जल स्रोतों का, जहां कुछ किया जा रहा है। हम इसी कामगार को अधिक भुगतान, कुछ बेहतर प्रशिक्षण से रख सकते हैं ताकि हम इस प्रक्रिया में परिसंपत्ति भी सृजित कर सकें। अब तक यह प्रतीत होता है कि हमने इसे एक जीविकोपार्जन योजना बनाकर रखा है और हम पा रहे हैं कि इसकी उपयोगिता सीमित है। कई खामियां भी रही हैं। उदाहरण के लिए, एक रिपोर्ट थी– और मैं मानता हूं कि यह सही रिपोर्ट थी कि अप्रैल– दिसंबर 2011 से संबंधित इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय में रोजगार की औसत दर और भुगतान 32 दिनों का था। इसलिए, इस योजना की उपयोगिता भी कम होगी। हमें प्रगतिशील होना होगा और इसे जीविकोपार्जन योजना के संदर्भ में आगे बढ़ने पर सोचना होगा किंतु इसे कुछ ऐसे क्रियाकलाप के साथ जोड़ना होगा जहां खामियां कम हों और जहां अवसंरचना सृजन का कुछ कार्य हो। महोदय, मैंने यह पहले भी सदन में कहा है और मैं इसे पुनः दोहरा रहा हूं। वित्तमंत्री ने बजट भाषण के पृष्ठ 7 पर निश्चितता के बारे में कहा है। उन्होंने यह अग्रिम मूलधन करारों के परिपेक्ष्य में कहा है। अब कर निश्चितता किसी भी कराधान योजना के लिए अनिवार्य है। निवेशक आते हैं तो उनको यह जानना चाहिए कि अर्जित राशि पर वे कितना कर अदा करने जा रहे हैं।

जब एक घरेलू निवेशक परियोजना शुरू करता है तो उसे यह जानना चाहिए कि कितनी अवधि के लिए उसे कर अदा करना है। एक के बाद एक वित्त मंत्री आए और उन्होंने भूतलक्षी योजना के इस सिद्धांत को अपनाया है। आप पहले वित्त मंत्री नहीं हैं और आप अंतिम वित्त मंत्री भी नहीं होंगे। किंतु मैं समझता हूं कि कभी न कभी हमें इस पर विचार करना चाहिए। कर योजना के इस आधुनिक युग में क्या भूतलक्षी प्रभाव से कर लगाना या कानून बदलना सही है? निर्यात बंद कर दिए गए हैं। लोगों ने अपने व्यवसायों एवं व्यक्तिगत आय की तदनुसार योजना बना ली है। इसलिए निवेश माहौल के दृष्टिकोण से यह एक ऐसा मुद्दा है जो सही संकेत नहीं दे रहा है।

अत्यधिक सेवा कर

महोदय, अब मैं सेवा कर के मुद्दे पर आता हूँ। वित्त मंत्री ने एक नियम बनाया है कि इस बार नकारात्मक सूची में आने वाली सेवाओं के अलावा सभी सेवाओं पर कर लगाया जाना है। इस बारे में मुझे तीन बिंदु रखने हैं।

कृपया, बजट को केवल राजस्व बढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में ही नहीं देखें। यह एक आर्थिक नीति दस्तावेज है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है, और इसलिए यदि आप अत्यधिक कर भार आरोपित करते हैं, और जैसा कि मैंने कहा आप 365 दिन और चौबीस घंटे, जो मैं अर्जित करता हूँ से जो मैं खर्च करता हूं जो मैं खाता हूं, जो मैं पहनता हूं, जहां मैं रहता हूं, जहां मैं गाड़ी चलाता हूं; प्रत्येक गतिविधि पर जो बारह प्रतिशत कर लगा रहे हैं वह बहुत अधिक है। आपने सभी सेवाएं इसमें ले ली हैं। अतः वित्त मंत्री को इस विषय पर पुनः गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। इसका एक मुद्रास्फीतिक भार होगा।

अब मैं, दूसरे बिंदु पर आता हूं। संविधान में सेवा कर के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से अवशिष्ट प्रविष्टि में आता है जो कि आपकी शक्ति है, केंद्र सरकार की शक्ति है। ऐसी सेवाएं, जो अन्यथा राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, जिन पर अब सेवा कर के लिए केंद्र द्वारा कर लगाया जाना है। राज्यों के पास सेवा कर आरोपित करने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन केंद्र के पास प्रथम सूची की प्रविष्टि 97, आपकी अवशिष्ट प्रविष्टि, के कारण यह है। अभी, जब आप राज्यों की सेवाओं पर कर लगा रहे हैं, तो क्या आप राज्यों को तद्नुसार प्रतिफल देने जा रहे हैं?

महोदय, अब मैं अपने तीसरे बिंदु पर आता हूँ, एक छोटा बिंदु, लेकिन कुछ ऐसा जो मेरी विचारशक्ति को खारिज कर देता है। मैंने इस नकारात्मक सूची का अध्ययन किया है। कानून के एक विद्यार्थी के रूप में, श्रीमान, करारोपण में, मैंने यह सीखा है कि गैरकानूनी गतिविधियों पर कर लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति तस्करी द्वारा धन कमाता है, तो उसे भी आय–कर अदा करना होगा। लेकिन, गैरकानूनी गतिविधियों को सामान्यतया छूट प्रदान नहीं की जाती। आपकी 17 की सूची में, आपने अजीब ढंग से, सट्टेबाजी, जुआ और लॉटरी को सेवा कर से छूट प्रदान की है। लॉटरी तो वैध है, लेकिन अन्य दोनों, मेरा मानना है कि इन्हें वास्तव में हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। नकारात्मक सूची में रखकर और यह कहते हुए कि करारोपण

के मामले में सट्टेबाजी और जुआ को भी मुक्त रखा जाएगा, उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं है।

शिक्षा का अधिकार और वित्तपोषण

महोदय, राज्यों के अधिकारों के संबंध में, मेरे पास एक या दो संक्षिप्त बिंदु हैं। आपने शिक्षा का अधिकार प्रदान करते हुए एक संवैधानिक संशोधन किया। राज्य यह पूछ रहे हैं: इसके लिए वित्तपोषण कौन करेगा? आपका आंरभिक प्रस्ताव यह था कि 75 प्रतिशत केंद्र सरकार से आएगा एवं 25 प्रतिशत राज्य द्वारा दिया जाएगा। राज्य इसमें कठिनाई महसूस कर रहे थे। आपके व्यय बजट में पृष्ठ संख्या 202 पर, मैंने यह पाया कि यह पूर्व में यह 75:25 था। बाद में यह कम हुआ और अब यह 50:50 होने जा रहा है। राज्यों के पास पहले से ही निधियों की कमी है और यदि यह 50:50 हो जाता है तो उनके लिए यह और भी अधिक कठिन होगा कि कैसे इसका वित्तपोषण किया जाए। इस प्रकार, हमारे पास एक ऐसा संवैधानिक संशोधन होगा जो मौलिक शिक्षा के अधिकार को, कम से कम प्राथमिक शिक्षा के लिए देता है। एक मौलिक अधिकार ऐसा होता है जो हमेशा प्रवर्तित किया जा सकता है। लेकिन, जब कोई व्यक्ति, इसके प्रवर्तन की मांग करता है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास निधियां नहीं हैं। इस प्रकार, जब हम लोकप्रिय नारों के संबंध में सोचते हैं, तो हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना हम उन्हें पूरा कर सकें। अतः जब आप इसे एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान करने के बारे में सोचते हैं, जो कि एक प्रवर्तनीय अधिकार था; आपके पास इसके कार्यान्वयन और अधिकार के प्रवर्तन के तरीके और साधन तथा निधियां होनी चाहिएं। अतः यदि राज्यों के हिस्से को काटा जाने वाला है, तो इससे आपको एक गंभीर समस्या होगी।

धन सृजन में संदेह

महोदय, तेल की कीमतों में कुछ और वृद्धि होगी क्योंकि कच्चे तेल का उपकर (सैस) 2500 प्रति मैट्रिक टन से 4500 प्रति मैट्रिक टन हो गया है। इस बजट में, आपने यह अनुमान किया है, और आपके वित्तीय घाटे के लिए यह एक समस्या पैदा करेगा। पूर्व के वर्षों में, आपने 3जी नीलामी के कारण लाभ उठाया है। इस वर्ष, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 122 लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। अतः आपके पास कुछ अधिशेष 2जी स्पेक्ट्रम हैं। आपको लोगों से उसका चार्ज भी करना है जो उन्होंने 6.4 मेगाहार्ट्ज की अधिकता में प्राप्त किया। अभी, आपने यह पूर्वानुमान किया है कि इस नीलामी से 58,217 करोड़ आएंगे। उस समय, 2जी का बहुत अधिक मूल्य था लेकिन जब 3जी बाजार में पहले से ही है और 4जी आने वाला है, तो कम से कम मुझे यह संदेह है कि किस प्रकार आप, आप द्वारा पूर्वानुमानित धन सृजित करने में सक्षम हो पाएंगे।

लेकिन अब, जब 3जी स्पेक्ट्रम पहले से ही बाजार में मौजूद है और 4जी आने वाला है, मुझे विश्वास नहीं है, कि किस प्रकार पुराना 2जी जो इन 122 लाइसेंसों से आएगा, उतने ही मूल्य का सृजन कर पाएगा। आपने कस्टम एक्ट (सीमा–शुल्क अधिनियम) को संशोधित किया है। कस्टम एक्ट में आपने धारा 104 को संशोधित किया है। पहले एक ऐसा समय था जब इस देश में बहुत अधिक तस्करी एवं कस्टम ड्यूटी का उल्लंघन होता था अतएव उस समय विदेशी विनिमय को संरक्षित करने की आवश्यकता थी। हमारे पास कानून थे। हमारे पास निवारक निरोध हैं। हम लोगों को जेल में डाल दिया करते हैं। अचानक, आज व्यवसाय वातावरण बदल गया है। लेकिन अभी भी हमें जागरुक होने की आवश्यकता है। मैं यह नहीं जानता कि किसने इसका सुझाव दिया और किसलिए धारा 104 संशोधित की जा रही है। सीमा–शुल्क अपराध तीन वर्षों के पश्चात् गैर–जमानतीय हो जाते हैं। यहां तक कि गैर–जमानती अपराधों में एक व्यक्ति जमानत की मांग कर सकता है। पहले हमें कानून के युवा विद्यार्थियों के रूप में जमानत के बारे में बताया गया, ना कि जेल के बारे में। मीडिया और न्यायालयों के परिवेश सिद्धांत हुआ करते थे, अब ये विपरीत हुए प्रतीत होते हैं। हमें यह गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते हैं, यहाँ तक कि अपराधियों के संबंध में भी। अभी आपने एक प्रावधान किया है, कृपया वित्त बिल में देखें। धारा 104 के संबंध में आपने जो प्रावधान किया है, वह यह बताता है कि जब कोई व्यक्ति जमानत के लिए आवेदन करता है, कोई भी न्यायाधीश उसे जमानत नहीं देगा। न्यायाधीश, सरकारी अभियोक्ता (पब्लिक प्रोसीक्यूटर) को एक नोटिस जारी करेगा। या तो सरकारी अभियोक्ता अपनी सम्मति देता है या यह कहता है कि मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि यह व्यक्ति बेकसूर है, दोषी नहीं है। अन्यथा, कोई जमानत नहीं होती। श्रीमान, यह प्रावधान 'पोटा' और 'टाडा' में मौजूद है और इसलिए उन्होंने कहा कि 'पोटा' और 'टाडा' में जमानत नहीं थी। जब आपकी सरकार ने 'पोटा' और 'टाडा' को निरस्त कर दिया, तो श्री चिदंबरम ने गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम में वापस संशोधन किए। एक जगह, जहाँ हमने कहा, कि कम से कम आतंकवादियों के लिए इस प्रावधान को रखें। आपने कहा, ''नहीं। हम बहुत उदार सरकार हैं। हम आतंकवादियों के लिए आसान जमानत प्रावधान चाहते हैं। हमारे पास आतंकवादियों के लिए एक केवल सामान्य जमानत होगी।''

अब, अचानक आपने 'पोटा' और 'टाडा' के जमानत प्रावधानों को बजट में, सीमा–शुल्क अधिनियम में खिसका दिया है।

चलिए हम एक उपयुक्त दिशा में बढ़ते हैं। यहां मूल्य वर्धन का विवाद हो सकता है। यहां, अपवंचन का प्रामाणिक मामला हो सकता है। लेकिन अपराधों की आनुपातिकता और उसके साथ कानून जिस ढंग से व्यवहार करता है, इन दोनों के बीच में कुछ ताल्लुक अवश्य हो सकता है। आपने एक बेमेल प्रावधान किया है। एक मक्खी को मारने के लिए आपको एक हथौडे की आवश्यकता नहीं होती, अतः इस तरह के प्रावधान, जो आपने बताए, आतंकवादियों के लिए लागू नहीं होने चाहिए, अभी आप कह रहे हैं ये प्रावधान सीमा–शुल्क अपराधों में लागू होंगे। धीरे–धीरे, जब आप इसे सीमा–शुल्क अपराधों में रखते हैं, प्रत्येक आर्थिक अपराधों में यह काम में आना प्रारंभ हो जाएगा।

मैं, आपसे यह कह सकता हूं कि इससे अच्छा कोई ओर परामर्श आप भारतीय व्यवसाय को नहीं दे सकते, भारत में निवेश नहीं करें क्योंकि यदि आप करते हैं, तो ये परिणाम होने वाले हैं। कृपया गंभीरतापूर्वक पुनः इस पर विचार करें। प्रत्येक कानून न्यायसंगत होना चाहिए। ऐसे लोग जो सीमा–शुल्क कानून का उल्लंघन करते हैं उनसे अवश्य रूप से निपटना चाहिए। लेकिन उन्हें आनुपातिक रूप से सुलझाना चाहिए। उन्हें एक ऐसे कानून के साथ सुलझाया नहीं जा सकता जिसे आतंकवादियों के लिए आपकी सरकार द्वारा कठोर समझा जाता था। अतः कृपया इन घटकों पर पुनः विचार करें।

अंत में माननीय वित्त मंत्री से मेरी यह अपील है। मैं, दो आधारों पर इस स्थिति के साथ सहानुभूति रख सकता हूँ। वह एक कठिन वातावरण में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की योजना बना रहे हैं। कोई और व्यय का निर्णय करता है और उसे कर वसूल करना होता है। हमारे यहां एक ऐसा राजनीतिक वातावरण है जो आम राय बनाने में बहुत अधिक प्रेरक नहीं है। ये उनके समक्ष चुनौतियाँ हैं। लेकिन, कम से कम इस बजट अर्थव्यवस्था को व्यवसाय अनुकूल बनाएं। आज, विश्व में कोई भी, एक भी व्यक्ति इस बजट से सही संकेत (दिशा) प्राप्त नहीं करता।

अतः कृपया आपके कुछ प्रावधानों पर पुनः विचार करें ताकि अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ने में हम वास्तव में मदद कर सकें। बहुत–बहुत धन्यवाद महोदय। ■

बजट में यूपीए सरकार का गरीब विरोधी चेहरा साफ झलकता है : प्रभात झा

गत 27 मार्च 2012 को राज्यसभा में आम बजट पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद व मध्यप्रदेश भाजपाध्यक्ष श्री प्रभात झा यूपीए सरकार पर जमकर बरसे। श्री झा ने वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, "आपने सब चीजें महंगी कर दी है और उसके बाद आप कहते हैं कि यह बजट आम जनता के लिए है।" श्री झा ने कहा कि बजट में किसानों, गरीबों, मजदूरों, महिलाओं, विद्यार्थियों, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ नहीं किया गया है। हम यहां श्री प्रभात झा द्वारा दिए गए भाषण का संपादित पाठ प्रकाशित कर रहे हैं :

एक माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस देश का आम बजट कितना शानदार है, यह इस सदन में सदस्यों की उपस्थिति तथा दर्शक दीर्घा में दर्शकों और पत्रकारों की उपस्थिति साफ–साफ बता रही है। मुझे नहीं लगता है कि इस पर बहस करने की कोई आवश्यकता होगी।

मैं इस पूरे सदन की बात कर रहा हूं, और इस पर बहस करने के बजाय प्रणब जी को स्वयं देखना चाहिए कि उदासीन बजट से लोग कितने उदासीन हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह बजट किसके लिए था? क्या यह बजट किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्र–छात्राओं के लिए, बच्चों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए था? आप इन सब चीजों को ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन आपको कहीं पर भी इस

तरह का कोई भी प्रमाण नहीं मिलेगा कि आपने इन वर्गों के लिए क्या किया है। क्या इनको कुछ दिया है? अगर कोई ईमानदारी से इस पूरे बजट को और प्रणब मुखर्जी जी के भाषण को पढ़े तो मैं नहीं समझता कि इन वर्गों के लिए कुछ किया गया है। मैं बाद में सोचने लगा कि आखिर क्या वजह है जो ऐसा बजट आया। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, मुझे ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, मुझे सीधे–सीधे लगा कि हाल ही की तो बात है जब बिहार में पिटाई हुई, उत्तर प्रदेश में हालत खराब हुई और प्रणब जी भी तो आखिर नेता हैं।

यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। बिहार में और उत्तर प्रदेश में जो हालत है, वह आपने देखी। आखिर प्रणब जी भी कम–से–कम मनुष्य हैं, क्या उन पर इसका असर नहीं पड़ेगा? आप किसी आदमी का खून निकाल लीजिए, उससे दौड़ने के लिए कहिए और फिर कहिए कि उसको फर्स्ट आना है, अब यह तो सम्भव है ही नहीं। हालत यह हो गई है कि मार भी खा रहे हैं और मारने वाला कह रहा है कि रोओ मत। अब यह तो कभी हुआ नहीं। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा उदासीन आम बजट, आज से पहले 80 बार बजट प्रस्तुत हुआ है, इस सदन ने कभी नहीं देखा। मैं जानता हूं, मैं इसीलिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि उस बजट में कही गई बातों को बोलना यहां पर मेरी ड्यूटी है और उसकी कमजोरियों को उजागर करना मेरा दायित्व है। इसलिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। देखिए, एक–दो राज्य हों, तब और बात है। आप राज्य देखिए– गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कनार्टक, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। अगर दावा करें कि महाराष्ट्र, तो कोएलिशन, अगर दावा करें जम्मू और कश्मीर, तो कोएलिशन। आखिर करे क्या आदमी! तीन साल में पूरी गजक लुट गई। जनता कांग्रेस की विदाई करे, उसे सब जगह से हराए और फिर अगर जनता यह उम्मीद करे कि प्रणब दादा या कांग्रेस बहुत अच्छा बजट देगी, तो यह तो एकदम contrast है। यह सम्भव ही नहीं था। मैं जानता हूं कि प्रणब जी ने तो यहां पर लोकसभा में खड़े होकर बजट प्रस्तुत कर भी दिया, शायद उनकी जगह कोई और होता, जिसके पास प्रारम्भ से ही राजनीतिक अनुभव नहीं हो, जैसा प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जाता है, मैं नहीं समझता कि प्रणब मुखर्जी के अलावा कोई बजट प्रस्तुत कर सकता था। इसलिए मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं और कहता हूं कि वही एकमात्र कांग्रेस के नेता हैं, जिन्होंने इन विपरीत परिस्थितियों में, जब देश में कांग्रेस को भगाया जा रहा है, ऐसे में खड़े होकर कम–से–कम उन्होंने बजट तो प्रस्तुत किया। मैं उन्हें बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं।

आप किसी आदमी का खून निकाल लीजिए, उससे दौड़ने के लिए कहिए और फिर कहिए कि उसको फर्स्ट आना है, अब यह तो सम्भव है ही नहीं। हालत यह हो गई है कि मार भी खा रहे हैं और मारने वाला कह रहा है कि रोओ मत। अब यह तो कभी हुआ नहीं। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा उदासीन आम बजट, आज से पहले 80 बार बजट प्रस्तुत हुआ है, इस सदन ने कभी नहीं देखा।

उदासीन बजट

उन्होंने अपने बजट के भाषण में कहा है कि इस बजट को बनाने में मैंने दो बड़े लोगों का सहयोग लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने दो लोगों का सहयोग लिया है। उन्होंने कहा कि बजट में दो लोगों का मार्गदर्शन मिला है, एक सोनिया जी का और दूसरा प्रधानमंत्री जी का। इस बजट में कितना अच्छा मार्गदर्शन लिया गया है और कितना अच्छा समर्थन मिला है, यह उनके भाषण में कहा गया। अब यहां पर प्रणब मुखर्जी जी सीधे–सीधे अप्रत्यक्ष रूप से देश की जनता को साफ–साफ बता देना चाहते हैं कि आम बजट की खामियों के लिए केवल वे नहीं, बल्कि उनके दोनों मार्गदर्शक भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने यह बात क्यों कही? उन्होंने यह बात इसलिए की कि यह बजट उदासीन है और इसके लिए मैं अकेले जिम्मेदार नहीं हूं। मैंने जिनका मार्गदर्शन प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि मैंने दो से मार्गदर्शन लिया। अब जब आपने मार्गदर्शन लिया है, मैं कोई यहां अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मैं आपके आंकड़ों से ही आपको जवाब दे रहा हूं। आपने कहा है, हम मोटे तौर पर मोटी बात जानते हैं, 2011–12 में हम पर कर्ज था 4.36 लाख करोड़, अब उसके बाद 2012–13 में यह हो गया 4.79 लाख करोड़ और इस कर्ज का सबसे काला पक्ष यह है कि हम प्रति रूपया 18 पैसे ब्याज देते हैं। कितना अच्छा मार्गदर्शन, कितना अच्छा समर्थन! बजट की पोल तो तब खुल जाती है, मैं आपके सामने एक आंकड़ा देता हूं, 2012–13 के अनुसार सरकार के प्रत्येक एक रुपया में 29 पैसा बाजार से उधार लिया जाता है।

और मजेदार मामला यह है कि 1.00 रुपये में 18 पैसे तो ब्याज में दिए जाते हैं और अगर 29 पैसे उधार लिए जाएंगे, तो 0.29+0.18=0.47 रूपया। पूरे के पूरे बजट के 1.00 रूपये में से आपके जो 47 पैसे हैं, वे चले जाएंगे बट्टे खाते में। अब 53 पैसे में काम चलाना है। देश को बजट की असलियत बतानी चाहिए थी। देश को गुमराह नहीं करना चाहिए था। आंकड़ों की बाजीगरी से जमीनी हकीकत को दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपने औपचारिकता का निर्वाह

किया है। 2011–12 में कर्ज पर देश की निर्भरता 27 पैसे थी, जो 2012–13 में लगभग 30 पैसे के करीब हो गई है। यह कैसा मार्गदर्शन है? आपने यह कैसा समर्थन किया है? मैं एक–एक चीज पर आऊंगा।

किसानों को लाभ नहीं मिलेगा

स्वामीनाथन जी ने किसानों के बारे में जो बात कही है, मैं दावा नहीं करता हूं लेकिन मैं वित्त मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं और कुछ पूछना चाहता हूं। वित्तमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि मेरे लिए कृषि क्षेत्र प्राथमिकता का क्षेत्र बना रहेगा। आंकड़े सच बोलते हैं और जब हम आंकड़ों की हकीकत में जाते हैं, तो 2011–12 में 17.123 करोड़ से बढ़ा कर कृषि क्षेत्र में परिव्यय पर 2012–13 में 20.208 करोड़ कर दिया गया है। आबंटन में इस वृद्धि का लाभ किसको मिलेगा? इसका लाभ कृषि उद्योग को मिलेगा, कृषि व्यवसायियों को मिलेगा। किसी भी हालत में किसान को इसका लाभ नहीं मिलना है।

केन्द्र सरकार ने इस वर्ष उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी में भी कटौती जारी रखी है। जाहिर है कि इससे कृषि उत्पादकता प्रभावित होगी और किसानों द्वारा आत्महत्या करने का सिलसिला बंद नहीं होगा, बल्कि ज्यादा ही होगा। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी सदन में कृषि मंत्री, शरद पवार जी ने शिवराज सिंह चौहान जी की प्रशंसा करते हुए कहा था कि किसानों को कैसे आप 100 रुपए बोनस देते हैं! मैं सदन को बताना चाहता हूं, प्रति क्विंटल गेहूं पर मध्य प्रदेश सरकार 100 रुपये देती है, यह है किसानों के प्रति हमदर्दी। जी हां, समर्थन मूल्य के अलावा। केन्द्र ने समर्थन मूल्य 1285 रुपये घोषित किया है और हम वहां पर 1385 रुपये दे रहे हैं। यह है किसानों के साथ हमदर्दी। इतना ही नहीं, मैं चुनौती देता हूं, यदि आप में दम है तो आप भी ऐसा करके दीजिए, आप किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त दीजिए, तब समझेंगे कि आपमें किसानों के प्रति हमदर्दी है।

इसके आगे आइए। कौन सा ऐसा राज्य है जो किसानों को 1.00 रुपया ब्याज पर कर्ज देता है? उस राज्य का नाम है भाजपा शासित मध्य प्रदेश राज्य और वहां के मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान। मैं पूछना चाहता हूं, आप 3 प्रतिशत कर दीजिए, कहां गए किसानों से किए गए आपके वे खोखले दावे? विदर्भ का नाम बदल कर रख दिया गया है– आत्महत्या प्रदेश। कैसा राज्य संभालते हैं आप? आप हमें गुमराह करते हैं। हो सकता है, दुनिया का 'यूनिवर्सल ट्रूथ' होता हो– दो दूनी चार, लेकिन आपकी सत्ता की लाठी के आगे डर के मारे लोग बोल देते होंगे– दो दूनी पांच। लेकिन सत्य यही है कि दो दूनी चार ही होता है और इस सच्चाई को आप कभी समझ नहीं सकते।

अब और आगे आइए। क्या इस सच्चाई को प्रणब जी नहीं समझते हैं? मैं केन्द्र से मांग करता हूं कि यदि आप किसानों के असली हितैषी हैं, तो आइए, किसानों को प्रति क्विंटल पर 100 रुपये बोनस दीजिए, इसके अलवा घोषणा कीजिए कि हम 1 रुपया के ब्याज पर कर्जा देंगे। देश चिंतित है। देश के 27 फीसदी किसानों ने खेती करना बंद कर दिया है। 40 फीसदी किसान यह कह रहे हैं कि हमारे पास कोई 'आल्टरनेट' व्यवस्था नहीं है। अगर देश के 27 फीसदी और 40 फीसदी किसान, 67 फीसदी किसान इस देश में किसानी छोड़ देंगे, तो देश का क्या हाल होगा? अन्नदाताओं की यह स्थिति है, आपको इसे समझने की चिंता करनी चाहिए और आपको किसानों की भावना समझनी चाहिए।

1997 से लेकर 2006 तक जिस देश में 2 लाख किसानों ने आत्महत्या की हो, अगर उन किसानों पर यूपीए सरकार आम बजट में रहमोकरम नहीं करती है, तो वह किसानों के साथ अन्याय करती है।

युवाओं की उपेक्षा

अब हम आते हैं देश की उस आबादी पर जिसके संसाधन पर देश गर्व करता है, उसका नाम है– युवा। विकास के लिए युवा सबसे बड़ा संसाधन है। आने वाले वर्षों में भारत सबसे बड़ा युवाओं का देश होगा। यदि आंकड़ों को देखें तो 2016 में देश की लगभग आबादी युवाओं की होगी।

हम जानते हैं कि इस विशाल युवा समुदाय को यदि हमने समन्वित नहीं किया, इसका सही उपयोग नहीं किया और अगर यह गलत रास्ते पर चली गई, विनाश की ओर चली गई, तो यह शक्ति अपने आप में उपलब्धि होने के बजाए इससे देश का बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए, मैं बजट में आंखें गड़ा–गड़ा कर देख रहा था कि युवाओं के लिए क्या है? 2016 में देश की आधी आबादी बनने वाले उन युवाओं के लिए इसमें क्या दिया गया है, तो युवाओं के प्रति उदासीनता का भाव इस बजट में है। 2011–12 में 311.39 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन 2012–13 में क्या दिया गया? देश की आधी आबादी युवाओं की होने वाली है, लेकिन आपने इसे बढ़ाकर कितना किया, 430.02 करोड़ रूपए। आपने यह जो ऊंट के मुंह में जीरा डालने का काम किया है, उससे यह सम्भव नहीं है और मैं फिर से यह कहता हूं कि यह भटकते हुए नौजवानों को सम्भालने का काम नहीं है। उनको हम गलत रास्तों पर जाने के लिए बाध्य करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज उनकी जरूरत की जो चीजें हैं, जिसका उपयोग आज का युवा करता है, जैसे– मोबाइल पर बात करना है, रेस्टोरेंट में जाता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, फिल्म्स देखना चाहता है, कोचिंग में

पढ़ने जाता है, गिफ्ट देता है, आदि ये सभी चीजें जो युवाओं से जुड़ी हुई चीजें हैं, वे सारी–की सारी महंगी कर दी गई हैं। यह आपका कैसा बजट है? क्या यह युवाओं को आकर्षित करता है या उसे बाध्य करता है कुछ और करने के लिए? देश के युवा, जिन पर देश का भविष्य निर्भर होता है, आने वाली पीढ़ी जो कि युवा है, वे सारे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं? इस युवा पीढ़ी की चिंता यदि आप नहीं करेंगे तो उनका ही जीवन अंधकारमय नहीं है, आधी आबादी युवाओं की है, तो इस देश का भविष्य भी अंधकारमय होगा और अगर देश का भविष्य अंधकारमय होगा तो हम और आप क्या करेंगे, इसका अंदाजा लगा सकते हैं।

आधी आबादी से भेदभाव

सर, अभी मैंने किसानों की बात की और उसके बाद युवाओं की बात की। देश की आधी आबादी महिलाओं की है, नारी–शक्ति की है। मैं अब इस बात पर आता हूं। जब मैंने पूरे बजट को टटोला कि देखूं इसके बारे में कहां लिखा है? मैंने पिछले बजट को भी देखा कि उस भाषण में भी मैं देख लूं कि कुछ होगा। इसी वर्ष हमने 101वां राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है। उसमें राष्ट्रपति महोदया ने कहा था कि हमारे देश में महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव जारी है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम सम्बोधन में कहा था कि ''महिलाओं के विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू उनकी आर्थिक तथा सामाजिक पहलू उनकी आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा है। हमारे समाज में व्याप्त इन सामाजिक पूर्वाग्रहों का समाप्त करना जरूरी है, जिनके कारण लैंगिक भेदभाव होना शुरू हुआ है।'' यूपीए सरकार की नीतियों और घोषणाओं में पूरी तरह से लैंगिक भेदभाव हर जगह देखा गया है। सभी मंत्रालयों में जेंडर आवंटन के 30 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ है? 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार 'स्वयंसिद्ध' नामक कार्यक्रम देश में पूरी तरह से बंद है, आज वह कहीं नहीं चल रहा है। 2012–13 के बजट में तो उसका कहीं नाम ही नहीं है। इससे बड़ा क्या होगा? इस बजट में महिलाओं को आयकर में छूट की बात या किसी भी प्रकार का विशेष लाभ नहीं दिया गया है।

गरीबी विरोधी चेहरा उजागर

सर, अब आगे मैं गरीबों की बात करता हूं। 2012–13 के बजट में गरीबों की घोर उपेक्षा की गई है। केन्द्र की यूपीए सरकार का गरीब और कमजोर विरोधी चेहरा 2012–13 के इस बजट में साफ दिखने लगा है। अब देखिए कि भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती कर उनके साथ घोर अन्याय किया गया है। इसे 2010–11 के 9.5 प्रतिशत से घटाकर 2011–12 में 8.5 प्रतिशत कर दिया गया था।

यह किसकी सरकार है? यह न महिला की, न युवा की, न किसान की और न इस देश की आधी आबादी की सरकार है। भविष्य निधि पर ब्याज में कटौती का सीधा असर असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर पड़ता है। इस देश के असंगठित क्षेत्र में कामगारों की संख्या 48 करोड़ है। आपका यह बजट 48 करोड़ लोगों के ऊपर एक साथ भार डालता है। हम जानते हैं कि भारत में कांग्रेसनीत यूपीए सरकार गरीबों का जितना उड़ाती है, उतना आज तक किसी ने नहीं उड़ाया होगा।

महोदय, सुप्रीम कोर्ट में गरीबी रेखा के आंकड़े किसने प्रस्तुत किये? अभी योजना आयोग ने प्रस्तुत किया है। मैं तीन चेक्स बनवाए थे, एक चेक प्रधानमंत्री जी के नाम, एक चेक चिदम्बरम जी के नाम और प्रणब मुखर्जी के नाम। मैंने उनको भेजा था कि आप कृपया इससे एक दिन का खर्चा चला लीजिए। आप गरीबी नहीं हटा सकते हैं, तो आपको गरीबों का मजाक उड़ाने का अधिकार किसने दिया? आप गरीबों का मजाक इस तरह से उड़ाएंगे? 1971 में इंदिरा जी ने कहा था ''गरीबी हटाओं'', क्या आपको उनका भी ध्यान नहीं है? अभी 5 करोड़ लोगों का नाम कैसे कम हुआ है? आप उस आधार को पढ़िए, जिसके आधार पर बीपीएल के नीचे रहने वाले लोगों का नाम दर्ज हो रहा है। अगर आपके घर में छोटा सा fan है, तो आप गरीब नहीं हैं। अगर आपने शौचालय में मिट्टी के ऊपर pot लगा दिया है, तो आप गरीब नहीं हैं। अगर आपका बेटा प्राइवेट स्कूल में जाता है, तो आप गरीब नहीं हैं। आपने इसको बना दिया है। यह एक साजिश है, इसलिए इस आर्थिक सर्वेक्षण की जांच होनी चाहिए।

महोदय, इन्होंने किस आधार पर कहा है कि आठ फीसदी गरीबी कम हुई है? आठ फीसदी कोई गरीबी कम नहीं हुई है, अगर आंकड़ों को उजागर किया जाए, तो आठ फीसदी गरीबी बढ़ी है। यह सरासर सदन को गुमराह किया गया है। मैं जानता हूं कि मेरे प्रदेश में 72 लाख लोग बीपीएल के नीचे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ 42 लाख लोगों को कोटा देती है। जिसके लिए वे लोग सवाल रकते हैं, लेकिन यहां एक साजिश की जा रही है और उनके नाम काटे जा रहे हैं। पूछने पर कहा यह जा रहा है कि आपके स्टेट के पटवारी हैं, आपके स्टेट के तहसीलदार हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि यह लगे कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार आपके नाम काट रही है, लेकिन हमने भी तय किया कि गरीबों की आवाज बन कर हम उठेंगे, गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे और इस से गरीबों को वाकिफ करेंगे। हमने उनके आंकड़ों को बतलाया है। आपने क्या किया है?

अभी महंगाई के बारे में बहुत सारी बातें हैं। आपने रोटी महंगी की है, कपड़ा महंगा किया है, मकान महंगा किया है, दवा महंगी की है, खाद महंगी की है, लोगों का घूमना महंगा कर

दिया है, कर्ज महंगा कर दिया है और उसके बाद आप कहते हैं कि यह आम जनता का बजट है! हमने कहा कि राय दीजिए और बजट लीजिए। हमने पूरे प्रदेश में जगह–जगह पर boxes रखवाए और जनता से कहा कि राय दीजिए और अपना बजट लीजिए। आपने किसकी राय ली, किससे राय ली? क्या आपने कोई राय ली? आप तो चर्चा तक नहीं करते। दुर्भाग्य से भारतीय राजनीति की प्रकृति इस तरह बदल रही है कि विरोधियों को अपना घोर दुश्मन समझ कर जिस तरह से उपेक्षा की जा रही है, यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की बात है। विरोधियों की बात को सुनना चाहिए। विरोधी भी कभी–कभी आपको सही बात बताते हैं। मैंने पत्रकारिता के जमाने में बहुत बड़े–बड़े दौर देखे हैं। मैंने अटल जी को विपक्ष में बैठे हुए देखा है और नरसिम्हा राव जी तथा इंदिरा जी को सत्ता पक्ष में बैठे हुए देखा है। उस समय जब कोई बात विपक्ष रखता था, तो उसका बारीकी से अध्ययन किया जाता था।

स्वास्थ्य व्यवस्था खस्ता हाल

अस्पताल की बात आई, एक लाख आबादी के अस्पतालों में सिर्फ 90 बेड्स हैं, एक लाख आबादी पर 60 डॉक्टर्स हैं, कायदे से एक लाख आबादी पर 140 डॉक्टर्स होने चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके लिए सरकारी खर्च के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का मात्र एक फीसदी रखा गया है। 2004 के भाषण में जो साझा पत्र जारी हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि मैं इसको जीडीपी का 2 से 3 फीसदी बढ़ा दूंगा। 2004 कहां और 2012 कहां, यह किसके साथ हो रहा है? सरकारी अस्पताल में कौन जाता है? सरकारी अस्पताल में गरीब लोग जाते हैं, बीपीएल कार्ड वाले जाते हैं, उनका मजाक उड़ाने का अधिकार आपको किसने दिया है? इसको आप कब करेंगे? यह हम जानना चाहते हैं। कपिल सिब्बल जी कितना हांकते रहते हैं, ये आंकड़े आपके हैं, मैं कोई घर से नहीं लाया हूं।

ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था

महोदय, देश की शिक्षा की हालत पर नजर डालते हैं, तो मन कचोट जाता है और लगता है कि ज्यादती हो रही है। अब देखिए, नए आईआईटी खोले गए, नए आईआईएम खोले गए, स्थानीय तौर पर एनआईटी खोले गए, लेकिन आज किस अभाव से जूझ रहे हैं? मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस बार उच्च शिक्षा में 30 हजार करोड़ रूपए चाहिए थे। आपने उनको क्या दिया?

आपने उनको 15,458 करोड़ रूपये दिए। यह उनकी हालत है! बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून के मद्देनजर पिछली बार सर्व शिक्षा अभियान के बजट में 40 प्रतिशत का इजाफा हुआ था, लेकिन इस बार इसमें सिर्फ 21.5 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, यह किसका है?

अब आप एक चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए। सरकार ने पिछले बजट में 6000 मॉडल स्कूलों को खोलने की बात कही थी और कहा था कि उस पर हम 1200 करोड़ रूपये खर्च करेंगे, लेकिन स्थिति क्या है? वर्ष 2008 में जो स्कूल बनने शुरू हुए थे, उनकी स्थिति यह है कि 6000 में से सिर्फ 438 स्कूल्स ही बने हैं। पीपीपी मॉडल में खुलने वाले स्कूलों की संख्या 2500 थी, लेकिन मुझे कहते हुए दुःख हो रहा है कि उसकी तो कोई योजना और कोई तंत्र ही नहीं बना। यह कैसा है? यह किसको दे रहे हैं? इस देश को देने वालों, जनता तुम्हें बार–बार बताएगी। उच्च तकनीकी आधार पर आइए, तो आईआईटीज की हालत ऐसी है।

यूपीए की वादाखिलाफी

वित्त मंत्री जी ने जो वादा किया था, उन्होंने किस तरह से पांच बातों पर वादाखिलाफी की है, उसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। उन्होंने पिछले बजट भाषण में कहा था कि हम 9 फीसदी विकास दर हासिल करेंगे। कहां गया उनका दावा? विकास दर सिर्फ 6.9 फीसदी! हम जानना चाहते हैं कि वह कौन सी बात थी? हम किसी घोटाले की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे।

वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम विनिवेश से 40 हजार करोड़ रूपये जुटाएंगे, जबकि आपने सिर्फ 14 हजार करोड़ रूपये जुटाए। आप किस मुंह से इस सदन को जवाब देंगे, यह हम जानना चाहते हैं। आपने कहा था कि सरकारी खर्च 3.4 फीसदी तक सीमित करेंगे, लेकिन अप्रैल से दिसम्बर महीने के बीच ही कुल सरकारी खर्च बढ़ कर 13.9 फीसदी तक पहुंच गया। वित्त मंत्री जी, हम जानना चाहते हैं कि यह आपका कैसा बजट है?

वित्तमंत्री जी ने कहा था कि सब्सिडी बिल घटा कर 12 फीसदी तक लाएंगे, लेकिन सब्सिडी की रकम अनियंत्रित होकर 2500 अरब रूपये पहुंचने के आसार हैं, जो कि अनुमान से 1000 अरब रूपये ज्यादा है। माननीय वित्तमंत्री जी, सदन इसके बारे में जानना चाहता है। वित्तमंत्री जी ने कहा था कि उधारी पांच फीसदी तक कम कर देंगे, लेकिन बड़े खर्च को पूरा करने में कुल उधारी 4.7 लाख करोड़ तक पहुंच गयी।

सर, ये चार लाइंस हैं:

सत्ता का यह राजमुकुट, कब किसकी रही बपौती,
लोकतंत्र में जनादेश है सबसे बड़ी चुनौती,
इन चुनौतियों के अवसर पर सुनो समय की भाषा को,
कथनी और करनी से पूरा करो राष्ट्र की आशा को।

नहीं तो, जनादेश जो देती है, वह जनादेश छीन भी लेती है और छीनने का वक्त आ गया है। जय हिंद, जय भारत। ■

निराशाजनक है यह बजट : पीयूष गोयल

गत 26 मार्च 2012 को राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष व सांसद श्री पीयूष गोयल ने यूपीए सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि मध्यवर्गीय और आम आदमी देश में एक के बाद एक हो रहे घोटालों से अचंभित और शर्मिंदा है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एक बार फिर से ऐसी स्थिति आ जाएगी जबकि भारत एक बार फिर से पिछड़ जाएगा और पिछले कुछ वर्षों में हमने जो अच्छी गति हासिल की है हम उसे गंवा देंगे। हम यहां श्री पीयूष गोयल द्वारा अंग्रेजी में दिए गए भाषण का हिन्दी रूपांतरण प्रस्तुत कर रहे हैं :

माध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। आरंभ में ही, महोदय, मैं निराश हुआ हूं। हमारे पास एक मेधावी और अनुभवी वित्त मंत्री हैं। पहली बार उन्होंने बजट 1981 में प्रस्तुत किया था, जब वे पहली बार वित्त मंत्री भी बने थे और तब से हम उनकी ओर अर्थव्यवस्था को संकट के दलदल से बाहर निकालने के लिए आशा की किरण के रूप में निहार रहे हैं। दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं है। महोदय, पूरे भारत में निराशा ही निराशा फैली हुई है। कार्पोरेट भारत को विश्वास ही नहीं है कि यह सरकार अर्थव्यवस्था पर हावी बुराईयों को समझती है।

मध्यम वर्ग पूरी तरह से दुखी है और एक के बाद एक लगातार हम घोटाले से पीड़ित होते जा रहे है, श्रीमान्, आम आदमी के बारे में सत्ताधारी पक्ष बड़ी भावुकतापूर्ण बातें करता है, परंतु वह इस सरकार द्वारा ढोल पीटने वाली कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विश्वास नहीं करता है, जिसे इतने वर्षों से एक विशेष परिवार के नाम पर आरंभ किया जाता है और जो प्रशासन की विफलता और भारी भ्रष्टाचारों की भेंट चढ़ जाता है, जैसा कि हमने स्वयं उनके स्तर के वरिष्ठ नेताओं के मुंह से 20–25 वर्षों से बहुत पहले सुनते भी आये हैं कि सरकार का 85 प्रतिशत खर्च तो भ्रष्टाचार और बदइंतजामी में नष्ट हो जाता है।

महोदय, इस सरकार को तो सुशासन के बड़े मुद्दे पर पाठ पढ़ना आवश्यक है। इसे तो खुदरा निवेश में एफडीआई पर अपना ध्यान देने की बजाय 'डिब्यूक्रेटाइजेशन' के बड़े मुद्दे का समाधान करना जरुरी है, क्योंकि दुर्भाग्य से इस सरकार के लिए रिफार्म का मतलब है एफडीआई और इससे आगे बढ़ना तो आसान नहीं है। मेरे विचार में इस सरकार को समझ लेना चाहिए कि हमारे देश में सुधारों के अलावा भी बहुत सी बातें हैं। लोग चाहते हैं कि उनके जीवन के साथ खिलवाड़ न हो। लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में हस्तक्षेप न हो, उनके जीवन के हर पहलू पर टैक्स न लगाया जाए, हर चीज पर लाइसेंस कोटा राज न थोपा जाये। वे उच्च करों के बोझ से मुक्ति चाहते हैं। वे अपने जीवन को ब्यूरोक्रेटिक नियंत्रण से बाहर होना चाहते हैं।

जीएसटी के लाभों को गंवा रही सरकार

श्रीमान् मैं और आगे बढ़ने से पूर्व सुधारों के बारे में एक–दो बातों पर चर्चा करना चाहूंगा। यह सरकार प्रायः आरोप लगाती है कि विपक्ष इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। महोदय, मैं इसे चुनौती देना चाहूंगा। हम जीएसटी की बातें करते हैं। सरकार जीएसटी शुरु कर अप्रत्यक्ष कर ढांचे में सुधार की बात करती है। परन्तु उसने इस दिशा में किया क्या है? सरकार पिछले चार वर्षों से वित्त मंत्री की एम्पावर्ड कमेटी पर काम कर रही है। पिछले चार वर्षों में सरकार अपने ही शासन वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भी केन्द्र सरकार द्वारा जीएसटी को कियांवित करने की शर्तों पर मना नहीं पाई है।

इस बारे में, जीएसटी के बारे में कुछ बातें उठाना चाहूंगा। हमारा विवाद इस बारे में नहीं है कि ऐसी केन्द्रीय कर–व्यवस्था हो जिससे इस व्यवस्था में होने वाली 'डुप्लीकेशन' से बचा जा सके। इससे करों पर निरंतर हो रहे प्रभावों को समाप्त किया जा सकेगा। संभवतः इसके स्थान पर जीएसटी लाने से राज्यों को सर्विस टैक्स का शेयर भी मिल सकेगा, जिसका सरकार ने उस समय वायदा किया था जब सर्विस

टैक्स पहली बार लगाया गया था कि राजस्व को राज्यों के साथ बांटा जायेगा। किन्तु, आज तक भी, हमने राजस्व को बांटते नहीं देखा है। किन्तु इस सभी लाभों के बावजूद भी, हम क्यों जीएसटी के लाभों को गंवा रहे हैं? जीएसटी कमेटी वह कॉमन फार्म भी तैयार नहीं कर पाई जिसे एसेसी को फाइल करना है। केन्द्र सरकार सभी शक्तियां हड़प लेना चाहती है। राज्य अपनी शक्तियों से हाथ नहीं धोना नहीं चाहते हैं। फिलहाल, लगभग दो लाख ' एसेसी एक्साइज में केन्द्र सरकार को रिपोर्ट करते हैं जबकि राज्यों के बुरी जुरीडिक्शन में 50–60 लाख एसेसी हैं। तो अब एक नया फार्मूला आया है, जो मैं नहीं समझता कि इस नये एसटी के बारे में लोगों को इस फार्मूले का पता भी नहीं है। फार्मूला यह है कि जनरल सेल्ज़ टैक्स के दो भाग होंगे, एक, सेंट्रल जीएसटी और दूसरा, स्टेट जीएसटी। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे जीएसटी का क्या लाभ होगा, जिसका प्रस्ताव किया जा रहा है। और फिर, इस बारे में जरा भी स्पष्टता नहीं है। एसेसमेंट कैसे होगा, रिटर्न कहां फाइल होगी, पैसा कैसे दिया जायेगा, ड़ीलर किसे रिपोर्ट करेगा और भी इसी तरह की कई बातें। और मुझे बताया गया है कि हर डीलर के दो एसेसमेंट किये जायेंगे, एक सेंट्रल अथारिटी की तरफ से दूसरा राज्य की तरफ से। और फिर, इसमें विवाद सुलझाने का कोई तंत्र नहीं है। अभी तक, हमें मालूम नहीं है कि एम्पावर्ड कमेटी के विवाद का कैसे समाधान होगा क्योंकि केन्द्र वीटो पावर चाहता है, जब तक कि जीएसटी के कार्यान्वयन या विवाद समाधान के समय, स्पष्ट है कि राज्य ऐसा नहीं होने देना चाहते।

महोदय, सरकार ने तो अभी यह तय नहीं किया कि किस दर पर जीएसटी लगेगा। फिर भी, दो दरों की चर्चा है, परंतु हम नहीं जानते, ये दो दरें क्या होंगी? हम नहीं जानते कि फ्लोर रेट क्या होगा, हम नहीं जानते कि वह बैण्ड क्या होगा जिस पर जीएसटी को विभिन्न राज्यों में लागू किया जायेगा। हम यह नहीं जानते कि क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को पैसा कैसे पहुंचाया जायेगा ? केन्द्र सरकार अभी तक जीएसटी के नुकसान पर राज्यों की क्षतिपूर्ति नहीं कर रही है, जो चार प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत कर दी गई है। जबकि वायदा यह था और यह पूर्ण विश्वास दिलाया गया था कि नुकसान की भरपाई की जायेगी। इस वर्ष, क्षतिपूर्ति की कोई योजना नहीं है और तर्क यह दिया जाता है कि जब हम वैट या सीएसटी लगाने की घोषणा की थी तब हमने कहा था कि हम दो या तीन वर्ष तक क्षतिपूर्ति करेंगे।' परन्तु, महोदय, सरकार ने यह भी कहा था कि जीएसटी का कार्यान्वयन तीन वर्ष में हो जायेगा। सरकार ने सौदे का हिस्सा पूरा नहीं किया। उसने जीएसटी कार्यान्वित नहीं किया, परंतु उसने राज्यों को क्षतिपूर्ति रोक दी। ऐसे कोई राज्य कैसे इस सरकार पर विश्वास कर सकता है? और स्पष्ट है कि इसका विरोध हुआ क्योंकि सरकार द्वारा प्रस्तावित इस प्रकार की जीएसटी व्यवस्था से राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता खतरे में पड़ गई।

हमारे पास एक मेफ्रावी और अनुभवी विद्वा मंत्री हैं। पहली बार उन्होंने बजट 1981 में प्रस्तुत किया था, जब वे पहली बार विद्वा मंत्री भी बने थे और तब से हम उनकी ओर अर्थव्यवस्था को संकट के दलदल से बाहर निकालने के लिए आशा की किरण के रूप में निहार रहे हैं। दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं है। महोदय, पूरे भारत में निराशा ही निराशा फैली हुई है। कार्पोरेट भारत को विश्वास ही नहीं है कि यह सरकार अर्थव्यवस्था पर हावी बुराईयों को समझती है।

अतः महोदय, जीएसटी मेरे सिर पर बोझ नहीं है यह केन्द्र सरकार के सिर पर बोझ है कि वह इन मुद्दों का समाधान करे, वह संबंधित लोगों और संबंधित राज्यों के साथ बैठे और समाधान निकाले।

प्रत्यक्ष कर संहिता का भयावह प्रावधान

महोदय, हमारे पास एक बड़ा सा कानून है जिसे 'प्रत्यक्ष कर संहिता' कहा जाता है, जिसका प्रस्ताव इस सरकार ने किया है। मैं स्थायी समिति का सदस्य हूं और हमने हाल ही में अपनी सिफारिशें की है और रिपोर्ट दी है। महोदय, यह सिफारिशें डीटीसी की विस्तृत जांच के बाद निकली है। परन्तु सरकार है कि वह कुछ चुनिंदा हिस्सों का चयन करती है, उदाहरण के लिए, जनरल एंटी–एंवाइडेंस लॉ और बजट मूलरूप में कियांवित करती है। ये भयावह प्रावधान हैं। सामान्य तौर पर, हम इनका स्वागत करते क्योंकि ये प्रावधान काले धन के लड़ने का साधन होते। परन्तु, हम सभी जानते हैं और मैं समझता हूं कि इस सदन के बहुत से सदस्यों को अनुभव है कि इस सदन के बहुत से सदस्यों को अनुभव है कि इस देश में टैक्स लॉज का दुरुपयोग किया जाता है। लोगों के सिर पर बन्दूक रखकर कहा जाता है कि 'देखो, आप 31 मार्च से पहले अतिरिक्त कर जमा करा दो, वर्ना तुम पर जुर्माना लगेगा, मैं आपको संकट में डाल दूंगा। क्योंकि हमें तो वित्त मंत्रालय द्वारा दिये गये लक्ष्य को पूरा करना है। महोदय, 'एसेसीज' को यह भी कहा जाता है कि 'आप 31 मार्च से पहले पैसा जमा

करा दो और हम अप्रैल में आपका पैसा रिफंड कर देंगे। परन्तु, यदि आपने ऐसा नहीं किया और यदि मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, तो मुझे मेरी पसंद की पोस्टिंग नहीं मिलेगी, फिर मेरी सीट खराब हो जायेगी और मुझ पर दण्ड़ लगेगा।''इस तरह हमारे देश में टैक्स – प्रशासन चलता है ? ऐसी स्थिति में, जीएएआर जैसे प्रावधान होने पर 'एसेसी' के साथ क्या बीतेगी? वे निरंतर दबाव में रहेंगे और कोई कानून मदद करने नहीं आयेगा। मैं मानवीय वित्त मंत्री से अनुरोध करुंगा कि आप बजट प्रावधान को अंतिम रुप देने से पूर्व स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार कीजिए और उन्हें जीएएआर प्रावधानों में शामिल कीजिए, जैसा कि इनमें प्रस्ताव है।

विनिवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएं

महोदय, इस सरकार के शासन में विनिवेश प्रकिया एक बड़ी केज्युलिटी बन कर सामने आई है। एनडीए सरकार ने अत्यंत पारदर्शी ढंग से नीलामी के माध्यम से स्ट्रेट्रेजिक बिक्री की प्रक्रिया शुरु की थी। मैं नहीं जानता कि किस प्रकार से सत्ताधारी बैंचों के सदस्यों ने इसे 'स्वीट–हार्ट ड़ील' की संज्ञा दी है। मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से कोई भी नीलामी, जिसमें पूरे विश्व को भाग लेने का आमंत्रण दिया जाता है, 'स्वीट–डील' कही जा सकती है। परन्तु, जब से यह सरकार सत्ता में आई है, किसी भी नुकसान उठा रही पीएसयू के शेयरों की इक्का–दुक्का बिक्री हुई है जो पिछले तीन वर्षों के विनिवेश लक्ष्यों तक भी नहीं पहुंच पाई। समाधान क्या है? मैं माननीय वित्त मंत्री के अनुरोध करुंगा कि सरकार के हाथों में इतने बड़े 'एसेट्स' पर निगाह डाले। आज, सूचीबद्ध पीएसयू की मार्केट कैप 14 लाख करोड़ रुपये की है। बाकी सभी अन्य पीएसयू की कुल मिलाकर कर संपत्ति 20 लाख करोड़ रुपये का संपत्ति आधार है। यह बात पहले ही मालूम है सरकार 51 प्रतिशत तक विनिवेश कर सकती है। आप क्यों नहीं इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हैं! आज क्यों नहीं वैकल्पिक मैकेनिज्म से राजस्व इक्ट्ठा करने की प्रक्रिया शुरु करते हैं, जैसा कि विपक्ष की माननीय नेता ने पारदर्शी ढंग से नीलामी का माध्यम सुझाया था। देश की संपत्ति का बेहतर उपयोग या दोहन प्राइवेट सेक्टर के हाथों हो सकता है, पब्लिक–प्राइवेट पार्टनर किसके माध्यम से हो सकता है। मैं सरकार से अनुरोध करुंगा कि वह और अधिक पूर्ण रूप से विनिवेश पर गौर करे और प्रक्रिया को आगे बढ़ाये।

महोदय, मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार को अधिकतर लेखांकन की प्रोद्भूत (एक्रूवल) व्यवस्था अपनानी चाहिए। इससे वह पहले वाली समस्या का समाधान हो जायेगा जिसका मैंने वर्ष के अंत में मात्र राजकोषीय लक्ष्यों को पूरा करने की खातिर एसेसियों को संकट में ड़ाला जाता है। सरकार के लिये यही अवसर है कि वह अपनी संपत्ति, व्यय और आय का लेखांकन प्रोद्भूत आधार पर शुरु करे जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार है, जो सरकारी राजस्व के खातों का सही ढंग भी है।

महोदय, हमारे प्रिय मित्र माननीय श्री मणिशंकर अय्यर ने बहुत चुनिंदा ढंग से एक ऐसा आंकड़ा चुना जो इस सरकार, या दुर्भाग्य से समग्र रूप में भारत के लिए एक पूर्ण विनाश का द्योतक है।

उन्होंने 'डेब्ट–टू–जीडीपी' का आंकडा चुनकर यह बताने की कोशिश कि किस प्रकार से भारत का 63 प्रतिशत डेब्ट–टू– जीडीपी अनुपात का इतिहास है, और बताया कि किस प्रकार से चीन के दिलचस्प और हैरतंगेज आकंडे हैं जो 155 प्रतिशत डेब्ट–टू–जीडीपी अनुपात बनते हैं। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने यह आंकड़ा कहां से प्राप्त किया। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करुंगा कि वे अपने आदरणीय सहयोगी को वास्तविक तथ्यों से अवगत करा दें। परन्तु, जो भी हो, मैं वास्तविक तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। सच यह है कि जबकि भारत का डेब्ट–टू–जीडीपी अनुपात 2011 में 66.2 प्रतिशत था, चीन का डेब्ट –टू–जीडीपी अनुपात 2011 में 16.5 प्रतिशत था। महोदय, आज व्यस्त हैं, इसलिए मैं उन्हें पुनः दोहराता हूं। चीन का डेब्ट–टू–अनुपात 2011 में 16.5 प्रतिशत था। मैं चाहता हूं कि ट्रेजरी बैंच के सदस्यों में और अधिक आर्थिक ज्ञान से संपन्न लोग सदन में, कम से कम सही आंकड़े प्रस्तुत करें। दुर्भाग्य से उन्होंने चीन जैसे देश को चुना, जिसमें लगभग हर पैरामीटर पर भारत को मात दी है, चाहे वह प्रतिव्यक्ति आय की बात हो, चाहे वह जीडीपी वृद्धि का मामला हो, चाहे वह एफडीआई हो और मैं कई और क्षेत्रों के नाम गिना सकता हूं। चीन ने भारत को खाली कर दिया है। और हमें अपने कामों को व्यवस्थित करना होगा। एवं हमें तेजी से काम शुरु करना होगा। यदि हमें भारत को सुपरपॉवर बनाने के सपने को साकार करना है तो मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करुंगा कि उन्होंने अपने बजट में जिन विशाल घाटे की राशि का प्रस्ताव किया है, उसे गंभीरता से लें और देश के संसाधनों को विशाल सब्सिडियों पर बर्बाद न करें, जो व्यर्थ जा रही है और उन्हें समुचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

एनडीए के समय था बेहतर अर्थव्यवस्था प्रबंधन

महोदय, इसी ढंग से विदेशी मुद्रा भण्डार के बारे में आज देश की वर्तमान स्थिति क्या है? पिछले वर्ष, वर्तमान खाता घाटा 3.4 या 3.5 प्रतिशत से अधिक था। 1947 –48 में भी, जब देश को स्वतंत्रता मिली, वर्तमान खाता घाटा

इतना चौंकाने वाला नहीं था। श्री मणिशंकर अय्यर ने एनडीए सरकार के प्रदर्शन का बहुत राग अलापा। अतः मैंने थोड़ा सा हिसाब लगाकर देखा। एनडीए सरकार 1998 में सत्ता में आई तो विदेशी मुद्रा भण्डार 29 बिलियन डॉलर था। जब उसने मार्च 2004 में सत्ता छोड़ी तो विदेशी मुद्रा भण्डार 113 बिलियन डॉलर था। इससे पता चलता है कि छह वर्ष की अवधि में 289 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि ने प्रतिवर्ष लगभग 48 प्रतिशत बैठती है। यह सरकार 2004 में सत्ता में आने पर उसके पास 113 बिलियन डॉलर का भण्डार था। आज, 16 मार्च 2012 को विदेशी मुद्रा भण्डार 294. 821 बिलियन डॉलर है अर्थात् अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के पिछले आठ वर्षों में लगभग 61 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे हमारे विदेशी भण्डार में प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैंने आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा है। प्रत्येक पृष्ठ पर मैं सांख्यिकीय विश्लेषण कर सकता हूं जिससे पता चलेगा कि एनडीए सरकार ने यूपीए सरकार के मुकाबले अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से प्रबंधन करके दिखाया। मुद्रास्फीति को ही लीजिये। मैं गलती सुधारना चाहूंगा। प्रणव दा ने अपना पहला बजट वर्ष 1982–83 में रखा था। महोदय, 1982–83 के बजट –भाषण के पृष्ठ 1 के पांचवे पैरे में, माननीय वित्त मंत्री ने कहा था – 'मुद्रास्फीति से लड़ाई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस मोर्चे पर प्रयासों में कोई भी सुस्ती हमारे विकास के आधार को ही कमजोर करेगी। मुद्रास्फीति से समाज के हर वर्ग को नुकसान पहुंचता है। परन्तु, यह कमजोर और अधिक गरीब लोगों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। मुद्रास्फीति से विकास प्रक्रिया को नुकसान पहुंचता है क्योंकि निवेश लागत बिगड़ जाती है। और वित्त –पोषण एक गंभीर बड़ी समस्या बन जाती है। तो हमें विश्वास दिलाया गया था कि उनके कारण पिछले दो वर्षों में प्रस्तुत बजटों में माननीय वित्त मंत्री का मंत्र होगा, जो मैंने देखे हैं।

एनडीए सरकार 1998 में सत्ता में आई तो विदेशी मुद्रा भण्डार 29 बिलियन डॉलर था। जब उसने मार्च 2004 में सत्ता छोड़ी तो विदेशी मुद्रा भण्डार 113 बिलियन डॉलर था। इससे पता चलता है कि छह वर्ष की अवधि में 289 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि ने प्रतिवर्ष लगभग 48 प्रतिशत बैठती है। यह सरकार 2004 में सत्ता में आने पर उसके पास 113 बिलियन डॉलर का भण्डार था। आज, 16 मार्च 2012 को विदेशी मुद्रा भण्डार 294. 821 बिलियन डॉलर है अर्थात् अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के पिछले आठ वर्षों में लगभग 61 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे हमारे विदेशी भण्डार में प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैंने आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा है। प्रत्येक पृष्ठ पर मैं सांख्यिकीय विश्लेषण कर सकता हूं जिससे पता चलेगा कि एनडीए सरकार ने यूपीए सरकार के मुकाबले अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से प्रबंधन करके दिखाया।

दुर्भाग्य से, मुद्रास्फीति के मोर्चे पर सरकार बुरी तरह से विफल रही है। यदि आप आंकडों को देखें, जब एनडीए सरकार सत्ता में 1998 में आई, तो उसने 'हैडलाइन इंफ्लेक्शन' अर्थव्यवस्था संभाली थी, जो 1991–96 की अवधि में पिछली कांग्रेस सरकार ने 9.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष का पहुंचा दिया था। 9.3 प्रतिशत से, यह सात वर्षों में सत्ता में रहते हुए यह घटकर प्रतिवर्ष 4.9 प्रतिशत आ गई थी।

हमने डब्ल्यू पी आई मुद्रास्फीति को घटाकर लगभग आधा कर दिया था। देश का दुर्भाग्य रहा कि यूपीए सरकार फिर से सत्ता में आई। पिछले सात वर्षों में 2011 तक, हैडलाइन इंफ्लेशन 6.2 प्रतिशत औसत की दर से वर्ष –दर–वर्ष फिर से बढ़ती चली गई। निश्चित ही, पिछले वर्ष की स्थिति सबसे बदतर थी। हमने पूरे वर्ष दो– अंकों में मुद्रास्फीति देखी, सिवाय पिछले दो महीने इसका अपवाद रहा, परन्तु वह भी आधार स्तर प्रभाव के कारण अधिक ही थी। यदि आधार पिछले वर्ष में अधिक होता है तो इससे पता चलता है कि मुद्रास्फीति कम हो गई है।

इसी प्रकार, खाद्य मुद्रास्फीति को लें, एनडीए शासनकाल में खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 3.5 थी, परन्तु इस सरकार के सात वर्षों में यह बढ़कर औसतन 10 प्रतिशत के दो अंकों तक पहुंच गई है। और यदि आप पिछले पांच वर्षों को लें, यह 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष बैठती है। अतः, आंकड़ों के रुप में ऐसे अनेक आंकड़े देखने को मिलेंगे जिनसे पता चलता है कि इस सरकार ने अर्थव्यवस्था का अत्यंत कुप्रबंधन किया है।

राजस्व प्राप्ति के मुकाबले ब्याज

महोदय, मैं उस एक आंकड़े पर आता हूं जिसका उल्लेख श्री मणिशंकर ने किया था और मुझे देखकर हैरानी होती है कि किस प्रकार से चुनिंदा ढंग से आंकड़े चुनकर सही तस्वीर को बिगाड़ा जाता है। वित्त मंत्री के बजट से उन्होंने राजस्व प्राप्ति के मुकाबले ब्याज देने की बात की। तो मैंने कैलकुलेटर से हिसाब लगाकर देखा देखा और पुरानी सूचना को इकट्ठा किया। महोदय, मुझे पता चला कि यह सरकार 1996 तक सत्ता में थी। इसने राजस्व प्राप्ति

के मुकाबले ब्याज का 47 प्रतिशत अनुपात छोड़कर गई और जब 1998 में एनडीए सरकार ने सत्ता संभाली तो हमें राजस्व प्राप्ति के मुकाबले ब्याज का 49 प्रतिशत अनुपात दर मिला। अतः, मूल कांग्रेस शासन के दौरान यह 47 प्रतिशत था, और जब एनडीए सत्ता में आई तो 49 प्रतिशत था। जब 2004 में हमने सत्ता छोड़ी तब तक हमारी पूर्ण राजकोषीय बुद्धिमत्ता के कारण हमने इसे 2004–05 के बजट अनुमानों में घटाकर 41 प्रतिशत पर ले आये, जिन्हें हमने वास्तव में प्राप्त किया। और, जैसा कि हमारे माननीय नेता ने उल्लेख किया है कि हमारे साथ ऐसा नहीं रहा था जैसा कि वर्तमान सरकार के साथ होता है कि यह ऐसे आंकड़े देती है जो कभी भी प्राप्त नहीं हो पाते हैं। हमारे आंकड़े प्राप्त किये जाते थे। हमने इसे कम कर 41 प्रतिशत पर ले आये। जो 16 प्रतिशत की कमी थी। परन्तु यहां पर भी वही बात कि यूपीए शासन के पिछले 6–7 वर्षों में, 2011–12 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, इन्हें कम करके 36 प्रतिशत पर लाया गया। और, जो घटकर 41 प्रतिशत से 36 प्रतिशत तक आया, जो केवल 12 प्रतिशत कमी दिखाता है। अतः हमारे मुकाबले कहीं बेहतर राजकोषीय स्थिति होने के बावजूद भी यह सरकार उतनी कमी नहीं ला सकी, जिस अनुपात में हमने कर दिखाई थी। अतः मैं चाहता हूं कि श्री मणिशंकर अय्यर अपने आंकड़ों को चैक करें, हो सकता है वे मेरे जैसे किसी व्यक्ति से सलाह कर सकते हैं, मैं आंकड़ों के माध्यम से उनकी मदद करुंगा और विकृत आंकड़े देने के बजाय और अधिक सही आंकड़े दूंगा। सबसे आश्चर्यजनक आंकड़े चीन वाले 155 प्रतिशत डेब्ट–टू– जीडीपी अनुपात वाले हैं। वे उनमें सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक हैं।

मेरी जानकारी में एक अत्यंत मनोरंजक आंकड़ा देखने को आया जब मैं विस्तार से बजट पढ़ रहा था क्योंकि वे हर बात पर एनडीए सरकार को दोषी ठहराते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एनडीए सरकार की कुछ उपलब्धियों को गिनाऊं, जो त्रुटियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। श्रीमान्, जब एनडीए सरकार 2004 में सत्ता में आई तो पिछले वर्ष में 2003–04 के लिए वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, जब हम सत्ता में थे, हमारा राजस्व पक्ष गैर–योजनागत व्यय 2,38,000 करोड़ रुपये था जबकि 2012–13 का वर्तमान बजट में सरकार ने राजस्व खाते को 8,65,000 करोड़ रुपये और पूंजीगत खाते को 1,04, 000 करोड़ रुपये कर दिया है।

अतः, सात वर्षों में सत्ता में रहते या अब 8 वर्षों में सरकार ने राजस्व खाते को बढ़ाकर 200 प्रतिशत तक पहुंचा दिया, जबकि पूंजीगत व्यय को बढ़कर 78,000 करोड़ रुपये से 4,20,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 100,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो 150 प्रतिशत बैठता है। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे साफ पता चलता है कि सरकार देश का पैसा लूट रही है, यह राजस्व खाते पर विशाल राजकोषीय घाटा पैदा कर रही है, जो देश को नुकसान पहुंचा रही है। और देश की भावी पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं पैदा कर रहा है। और मुद्रास्फीति ने किसी भी रूप में कल्पना करके भी बुद्धिमत्तापूर्ण राजकोषीय प्रबंधन नहीं कही जा सकती है। मेरे विचार में किसी भी अच्छी सरकार के लिए पूंजीगत खाते पर पैसा बर्बाद करने की बजाय देश के निर्माण के लिए पूंजीगत खाते पर अधिक पैसा खर्च करना चाहिए और इसके अलावा, मैं एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्री ने पिछले वर्ष के बजट में 14 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि को प्रोजेक्ट किया था और अब पुनः उन्होंने इस वर्ष के बजट में 14 प्रतिशत की बात कही है। अब उन्होंने पिछले वर्ष में 14 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की है, परंतु यह 'जेनुइन' वृद्धि नहीं है, सामान्य वृद्धि 14 प्रतिशत है और वास्तविक वृद्धि,जैसा उन्होंने स्वंय स्वीकार किया है, 6.5 प्रतिशत है,जिसे मैं निजी तौर पर चुनौती देता हूं क्योंकि यह आंकड़ा प्रथम तिमाही से बदतर है। जब तक हमें वास्तविक आंकड़े प्राप्त होंगे तब तक यह 6.9 प्रतिशत घटकर 6.5 प्रतिशत रह जायेंगे।

इतना कहने पर भी हमने 14 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त कर ली। तो ऐसा कैसे हुआ? बाकी सब मुद्रास्फीति था। अब, वर्तमान वर्ष में, हमें बताया गया है कि यह फिर से 14 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि होगी। मैं हिसाब लगा रहा था कि जीडीपी की वास्तविक वृद्धि इस वर्ष 7.6 प्रतिशत, 14 प्रतिशत सामान्य वृद्धि रहती है तो इसका मतलब आप पहले ही 7 प्रतिशत मुद्रास्फीति का बजट बना रहे हैं। चाहे फाइनल आंकड़े कुछ भी क्यों न हों, आज हम इसमें 7 प्रतिशत का बजट पहले से ही तैयार कर रहे हैं। मुझे शक है कि फाइनल आंकड़े फिर से दो अंकों की मुद्रास्फीति पैदा करेगी जिससे बड़े स्तर पर अप्रत्यक्ष करों पर दबाव पड़ेगा और मुद्रास्फीति द्वारा 'लोवर ग्रोथ' की क्षतिपूर्ति करेगी। हां, आपको जीडीपी में 14 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि फिर से मिलेगी, परंतु मुद्रास्फीति बढ़ेगी।

'कम सब्सिडी दिखाओ-बढ़ा राजस्व दिखाओ' का खेल

हां, सब्सिड़ी के रुप में, माननीय वित्त मंत्री जी ने बेहद कम प्रावधान किया जिस पर मुझे अत्यधिक हैरानी होती है कि बजट का सामान्य पाठक भी एक नजर में पहचान जायेगा– और यही बात मैंने पिछले वर्ष मार्च के अपने भाषण में ठीक यही बात कही थी, कि सब्सिड़ी कम करके दिखाई

है। इसके लिए किसी राकेट–विज्ञान की समझ की आवश्यकता नहीं है। परन्तु इस बार फिर से वही खेल है – कम सब्सिड़ी दिखाओ, बढ़ा राजस्व दिखाओ, जनता को मूर्ख बनाओ, क्योंकि अधिकतर जनता पिछले वर्ष के अनुमानों पर परेशान नहीं होती है। वह तो हो गया। वह पीछे की बात है, अब आगे देखो। तो आप लोगों को बताते हैं कि आगे तो बहुत अच्छा होने वाला है। भविष्य गुलाबी है, पिछली बातें भूल जाओ। 2013 में, जब हम फिर से बहस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि मेरी पार्टी मुझे बोलने का अवसर देगी तो हम फिर से एक तस्वीर देखेंगे, एक वास्तविक तस्वीर देखेंगे कि यह सभी आंकड़े गलत होंगे और कुछ कहने को नहीं बचेगा।

महोदय, सर्विस टैक्स एक क्षेत्र है जिसके बारे में माननीय वित्त मंत्री को बताना चाहता हूं कि जब बात बजट की होती है कि वे आंकड़ों के मामले में ईमानदारी नहीं कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि मुझे उनसे जवाब मिलेगा। मैंने कई अवसरों पर सभापति महोदय का संरक्षण प्राप्त किया है। पिछले एक–डेढ़ वर्षों में सदन में मैंने सातवीं या आठवीं बार हस्तक्षेप किया है, परन्तु आज तक मेरे उठाये गये प्रश्नों पर मुझे किसी भी बिंदु पर जवाब नहीं मिल पाया है। खैर, यह तो दूसरी बात रही। मुझे आशा है कि संसदीय प्रक्रिया में ऐसा कुछ तंत्र होना चाहिए जिससे हमारी प्रतिबद्धता का जवाब मिल सके। महोदय, वित्त मंत्री ने सर्विस टैक्स की वृद्धि को 95,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ दिखाया है, जो केवल 29,000 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाती है।

इस प्रोजेक्शन को इस रूप में दर्शाया है कि इसमें आम आदमी पर कोई बहुत बोझ नहीं पड़ेगा। महोदय, मैं इस आंकड़े को चुनौती देता हूं। और मैं आपको इसका कारण बताऊंगा।

महोदय माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि जीडीपी में वृद्धि 14 प्रतिशत होगी और हम सभी जानते हैं कि ये सर्विसेज बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इससे निम्न कृषि और मैन्यूफैक्चरिंग वृद्धि की क्षतिपूर्ति होती है। पिछले वर्ष सर्विस टैक्स 71,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 95, 000 करोड़ रुपये हो गया। यह दरों में बिना कोई वृद्धि किये 34 प्रतिशत रही। इस वर्ष और पिछले वर्ष भी, जीडीपी की वृद्धि 14 प्रतिशत होनी थी। इस तर्क के आधार पर, इस वर्ष भी, सामान्य रुप से, बिना कोई टैक्स दर बढ़ाये तथा बिना किसी अन्य क्षेत्रों में टैक्स लगाये सर्विस टैक्स में 35 प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए। किन्तु, और भी कम से कम करके देखें, मैं इसे 30 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि मानता हूं। अतः, यह स्थिति 95,000 करोड़ रुपये – 28,000 करोड़ रुपये से 30 प्रतिशत बनेगी, जिससे सर्विस टैक्स में सामान्य वृद्धि हो पायेगी। अब वित्त मंत्री ने सर्विस टैक्स का दायरा .भी बढ़ा दिया है,जिसमें 17 मदों को छोड़कर हर चीज पर टैक्स लगाया गया है। मेरा मानना है कि इससे अतिरिक्त 25 प्रतिशत जुड़ेगा। अतः विस्तृत दायरे से 32,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्राप्त होंगे। यह कुल जमा 1,55,000 करोड़ रुपये बनेगा। इसके बाद 20 प्रतिशत दर की वृद्धि हुई है, जो 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की गई है, जिससे अतिरिक्त 31,000 करोड़ रुपये मात्र सर्विस टैक्स से 1,86,000 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, जो आप देखेंगे कि इसका बोझ आम आदमी पर पड़ेगा। जैसा कि हमारे नेता ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने 1991 में यह बात कही थी कि लोगों पर अप्रत्यक्ष कर लगाने का रास्ता ऐसा है जो अक्षमता प्रदर्शित करता है,यह आम आदमी पर बोझ है, और इसका आश्रय नहीं लिया जाना चाहिए। परन्तु, हम देखते हैं कि आम आदमी पर 91,000 करोड़ रुपये का बोझ लादा गया है, जो 33,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि है और 44,000 करोड़ रुपये का उत्पादन शुल्क बढ़ी हुई वृद्धि आम आदमी पर अव्यावहारिक बोझ बन गई है।

क्या एनआरएचएम जैसी लूट देश में चलती रहेगी, न जानें कब आम आदमी तक स्वास्थ्य लाभ पहुंच पायेगा? पर्यटन के लिए बजट में क्या है? इंफ्रास्टौक्चर के लिए बाजार में क्या है, और जो कुछ हो रहा है, वह पुराने सुफ्फारों की बात हो रही है जिसके कारण 'सेज' स्टोरी का अंत हुआ था। विदेशी निवेश खत्म हुए थे और हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये थे कि जहां भारत फिर से पिछड़ेपन के पुराने दिनों में पहुंच जायेगा और पिछले कुछ वर्षों में हमने जो रतार पकड़ी है, वह रतार समाप्त हो जायेगी।

एक बात और भी। वित्त मंत्री वर्तमान वर्ष में 30 प्रतिशत की उत्पादन शुल्क वृद्धि की बात करते हैं। इसमें से 20 प्रतिशत तो बढ़ी हुई दर के कारण है। उनका कहना है कि संग्रहित उत्पादन शुल्क की वास्तविक वृद्धि केवल 10 प्रतिशत होगी। वह पहले की मान रहे हैं कि भारत में उत्पादन और मैनुफैक्चरिंग का काम ठप है। उन्हें घरेलू भारतीय मैनुफैक्चरिंग से कोई उम्मीद नजर नहीं आती। परन्तु सीमा शुल्क में बिना किसी दर की वृद्धि के 22 प्रतिशत की वृद्धि है। क्या हम आने वाले वर्षों में आयात पर जरुरत से कहीं अधिक तो निर्भर नहीं होने जा रहे हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से अस्त–व्यस्त हो जायेगी और

शेष पृष्ठ 26 पर

लोक सभा

यूपीए सरकार सच बोलने से बचती है : जसवंत सिंह

गत 22 मार्च 2012 को लोकसभा में आम बजट पर चर्चा की शुरूआत करते हुए पूर्व वित्त मंत्री एवं भाजपा सांसद श्री जसवंत सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने आम आदमी का पेट एवं जेब भरने की कोई व्यवस्था नहीं की है। सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों से लोगों के पेट नहीं भर सकता। ये आंकड़े भले ही महत्वपूर्ण हों लेकिन उन्हें हम देश की खुशहाली का पैमाना नहीं मान सकते। सरकार आम लोगों के पेट भरने की समुचित व्यवस्था करे। हम यहां श्री जसवंत सिंह द्वारा दिए गए भाषण का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं :

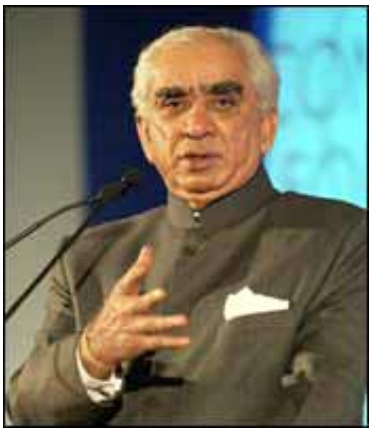

वर्ष के प्रारंभ में तीन वार्षिक चर्चाओं, राष्ट्रपति का अभिभाषण, केन्द्रीय बजट और रेल बजट में से मैं समझता हूं कि केन्द्रीय बजट पर चर्चा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वित्तीय नीति संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेज के मुख्य उद्देश्य और प्राथमिकता पर मेरा मत सरकार से भिन्न है। मैं वित्तीय नीति के सरकार के मुख्य उद्देश्य को नहीं जान पा रहा हूं। सरकार को घरों को, गृहणियों को और नागरिकों को और अधिक खर्च करने के लिए समर्थ बनाना चाहिए। आप जो भी काम करते हों, अधिक से अधिक उत्पादन करो और उत्कृष्ट गुणवत्ता बरकरार रखो। यह हमारी आर्थिक सोच थी। दूसरा मुद्दा है कि हमें आपस में बांटना चाहिए। बचपन में भोजन के दौरान हमें कहा जाता था कि गाय के लिए, चिड़ियों के लिए अलग से कौर रख दो। हम इसे भूल गए हैं। हम भारतीय तभी होंगे जब हम अपनी संस्कृति के मूल तत्वों को पुनः अपनाएंगे। तीसरा था बचत। हमारी अर्थव्यवस्था बचत–उन्मुखी नहीं रह गई है बल्कि हम उपभोक्तावादी हो गए हैं। दो और अन्तिम बिन्दु हैं। पहला है दान करना। सिर्फ भारत में ही गुप्त दान की अवधारणा है। राज्य को व्यापार पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। पेट्रोल कीमतों में शीघ्र वृद्धि करें। आप डीजल कीमतों में भी वृद्धि करना चाहेंगे। राजनीतिक रूप से यह लोकप्रिय नहीं होगा परन्तु आर्थिक और वित्तीय रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यों को विद्युत की चोरी को बिल्कुल ही समाप्त कर देने के लिए अवश्य ही सहयोग करना चाहिए। निवेश भी कम हुआ है।

घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया लगभग थम सी गई है। यह निश्चित रूप से कमजोर राजनीतिक नेतृत्व दर्शाता है। मुद्रास्फीति सर्वथा हानिकारक है। राज्यों एवं केन्द्र का कुल घाटा 9 प्रतिशत से अधिक है। यह बहुत ही नुकसानदायक है। राज्यों का वित्तीय घाटा कम हुआ है। वे चालू खाते पर ध्यान दे रहे हैं और केन्द्र उपभोग पर ध्यान दे रहा है जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। राष्ट्रीय आत्मविश्वास में कमी आई है क्योंकि सरकार सच बोलने से बचती है। इस बजट में 17 ऐसे विधान हैं जिनको भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना है। यह संख्या बहुत ज्यादा है। भारत में किसी भी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य न केवल गरीबी कम करना है अपितु इसे पूर्णतः समाप्त करना है।

कृषि भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारी संस्कृति का स्रोत है। भारत में विश्व का सर्वाधिक पशुधन, सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है जो अमरीका से ज्यादा है और चीन की तुलना में लगभग दुगुनी है। यह बहुत निराशाजनक है कि प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर उत्पादन तथा प्रति गाय का दूध या प्रति भेड़ ऊन का उत्पादन बहुत कम है। विश्व बैंक के 2005 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 75.6 प्रतिशत आबादी क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के आधार पर प्रतिदिन दो डालर से कम पर जीवन यापन कर रही है। 41.6 प्रतिशत आबादी नई अन्तर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा जो कि पीपीपी 1.25 है, से नीचे जीवनयापन कर रही है। हमारी अर्थव्यवस्था आधुनिक और आत्मनिर्भर होनी चाहिए जो विश्व के सबसे विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा कर सके। हमारे

नागरिकों को खुश और संतुष्ट होना चाहिए। इसके लिए गरीबी समाप्त करें और नागरिकों में नया जोश भरें। इसके लिए कृषि विकास सर्वोत्तम है। राजग सरकार द्वारा आरम्भ किए गए कुछ ग्रामीण विकास कार्यक्रम बहुत अच्छे थे। उनमें से एक शहरी संसाधनों का प्रावधान और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं देना था। इसे सिर्फ इसलिए समाप्त मत करिए क्योंकि इसे हमने आरम्भ किया था। सरकार को देश के बाहर किए जा रहे निवेश में वृद्धि और बाहर से देश में निवेश में कमी की चुनौती को हल करना चाहिए। पिछले वर्ष भारत के निवेशकों द्वारा विदेश में किया गया निवेश देश में आए। यह देश की उद्यमशीलता की क्षमता को दर्शाता है। परन्तु प्रयास करें कि यह उद्यमशीलता देश के लिए हो। जीडीपी आंकड़ों से पेट नहीं भरता है। इससे संतुष्टि नहीं मिलती है। यह हम सब के लिए एक चुनौती है जिसका हमें हल खोजना होगा।

घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया लगभग थम सी गई है। यह निश्चित रूप से कमजोर राजनीतिक नेतृत्व दर्शाता है। मुद्रास्फीति सर्वथा हानिकारक है। राज्यों एवं केन्द्र का कुल घाटा 9 प्रतिशत से अधिक है। यह बहुत ही नुकसानदायक है। राज्यों का वित्तीय घाटा कम हुआ है। वे चालू खाते पर ध्यान दे रहे हैं और केन्द्र उपभोग पर ध्यान दे रहा है जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। राष्ट्रीय आत्मविश्वास में कमी आई है क्योंकि सरकार सच बोलने से बचती है।

गंगा–यमुना हमारे देश की जीवन रेखा हैं। कृपया इन नदियों जो कि हमारी सभ्यता का मुख्य स्रोत है का प्रदूषण दूर करें। मनरेगा के कार्यान्वयन में बहुत भ्रष्टाचार है। इससे देश में पूरी श्रम प्रणाली ही बिगड़ गयी है चाहे औद्योगिक या फिर कृषि संबंधित। अंत्योदय योजना बहुत अच्छी योजना थी। इस मनरेगा पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। हर चीज की कमी है। सरकार की अक्षमता है, भ्रष्टाचार है और छोटा–मोटा भ्रष्टाचार भी है। बड़े भ्रष्टाचार के मामले तो हैं ही किंतु छोटा भ्रष्टाचार आम आदमी को सबसे अधिक प्रभावित करता है। मैंने पश्चिम राजस्थान में चरागाह विकास के लिए कुछ उपाय शुरू किए थे लेकिन उन्हें इस सरकार ने बंद कर दिया। यह योजना लद्दाख और हिमाचल तक भी पहुंचनी थी। कृपया उस पर ध्यान दें। दार्जिलिंग में राजमार्गों की स्थिति बहुत खराब है। वहां की रेललाईन भी हाल ही के भूकम्प में टूट गयी है। कृपया इन दोनों बातों पर ध्यान दें। हमें इस उपभोक्तावादी अर्थव्यवस्था और समाज से आगे बढ़ते हुए स्वदेशी की भावना को जागृत करना चाहिए।

यह भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमें सोच को बदलना पड़ेगा। उसके बाद हमें शासन व्यवस्था और राजनैतिक व्यवस्था में सुधार करना पड़ेगा। राजनेताओं और हमारी मौजूदा राजनीति ने हमारी अर्थव्यवस्था, देश और हमारे समाज को अगवा कर लिया है। हमें इस संक्रमण की परीक्षा की चुनौती का सामना करना चाहिए। ■

पृष्ठ 24 का शेष...

भारत के विशाल घरेलु बाजार की कीमत पर विदेशी अर्थव्यवस्था लाभ उठाएगी?

गरीबों को उच्च दर के कराधान से मुक्ति मिले

किन्तु, महोदय, आज की स्थिति में हम देखते हैं कि हम एक स्थिति पर पहुंच गये है जिसमें सरकार को सक्रिय कदम उठा कर गरीब लोगों की समस्याओं को सुधारना चाहिए, उन्हें उच्च दर के कराधान से राहत देनी चाहिए, उनके लिए स्वास्थ्य–लाभ के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए और उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके, इसका प्रबंध होना चाहिए। मुझे हैरानी होती है जब श्री मणिशंकर अय्यर ऐसे आंकड़े पेश करते हैं कि नौंवी कक्षा का विद्यार्थी दूसरी कक्षा के पाठ्य पुस्तक को भी नहीं पढ़ सकता है। मुझे नहीं मालूम है कि वह हमारी तरफ से बोल रहे थे या सत्ताधारी पार्टी की तरफ से। मेरे विचार में जिस सर्वशिक्षा अभियान के सराहना के पुल बांधे जाते हैं, उसे देखते हुए तो यह स्थिति आज की सत्ता में बैठी सरकार के लिए घोर अपमान है। क्या एनआरएचएम जैसी लूट देश में चलती रहेगी, न जानें कब आम आदमी तक स्वास्थ्य लाभ पहुंच पायेगा? पर्यटन के लिए बजट में क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बाजार में क्या है, और जो कुछ हो रहा है, वह पुराने सुधारों की बात हो रही है जिसके कारण 'सेज' स्टोरी का अंत हुआ था। विदेशी निवेश खत्म हुए थे और हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये थे कि जहां भारत फिर से पिछड़ेपन के पुराने दिनों में पहुंच जायेगा और पिछले कुछ वर्षों में हमने जो रफ्तार पकड़ी है, वह रफ्तार समाप्त हो जायेगी। बहुत– बहुत धन्यवाद, महोदय! ■

बजट में यूपीए का क्रूर चेहरा उजागर : यशवंत सिन्हा

गत 27 मार्च 2012 को लोकसभा में आम बजट पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद व पूर्व वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा ने यूपीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी से अपील की कि वह एक्साइज ड्यूटी सहित तमाम करों में बढ़ोतरी को वापस लें। हम यहां श्री यशवंत सिन्हा द्वारा दिए गए भाषण का संपादित पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं :

सभापति महोदय, इस देश की अर्थव्यवस्था की मौलिक समस्या क्या है? उसी की ओर सदन का ध्यान आकषित करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस देश की अर्थ व्यवस्था की मौलिक समस्या मुद्रास्फीति है । आज वित्त मंत्री जी को यह संतोष हो सकता है कि इंफ्लेशन हाल के महीनों में धीरे–धीरे नीचे आया है लेकिन फरवरी के जो आंकड़े आए हैं, उससे पता चलता है कि इंफ्लेशन फिर आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब इंफ्लेशन का दर अगर 7 और 8 प्रतिशत होता था तो हम लोगों को बहुत चिंता होती थी। आज हम लोग इस बात का उत्सव मनाते हैं कि इंफ्लेशन की दर 7–8 प्रतिशत नीचे आ गयी है और ़वित्त मंत्री जी खड़े होकर बोलते हैं कि 20 प्रतिशत थी और वहां से 7 प्रतिशत पर आ गयी है। इंफ्लेशन अगर केन्द्रीय मुद्दा है तो क्यों है? अगर आप पिछले कई वर्षों के आंकड़े उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि वर्ष 2007–2008 तक सबकुछ बिल्कुल ठीक था। वर्ष 2003 में मेरे काबिल दोस्त जसवंत सिंह जी इस देश के वित्त मंत्री थे।

2003–2004 में इस देश ने छलांग लगाई और हम तेजी से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढने लगे। इस देश ने छलांग लगाई और उसके बाद आप 2007–2008 का आंकड़ा उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि सब कुछ बढिया़ था। ग्रोथ रेट 9 प्रतिशत से ऊपर थी, फिसकल डेफिसिट कंट्रोल में था, रेवेन्यू डेफिसिट कंट्रोल में था, इंफ्लेशन रेट कंट्रोल में थी, सेविंग रेट आज तक उतनी नहीं हुई, 37 प्रतिशत इंवेस्टमेंट रेट से बढक़र 39 प्रतिशत हो गई। इस तरह से हम सब तेजी से आगे बढ़ रहे थे।

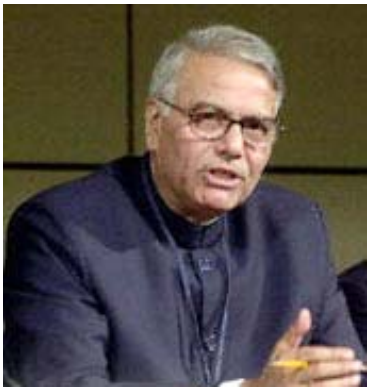

2003–2004 में इस देश ने छलांग लगाई और हम तेजी से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढऩे लगे। इस देश ने छलांग लगाई और उसके बाद आप 2007–2008 का आंकड़ा उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि सब कुछ बढिय़ा था। ग्रोथ रेट 9 श्तिशत से)पर थी, फिसकल डैफिसिट कंटौल में था, रेवेन्यू डैफिसिट कंटौल में था, इंलेशन रेट कंटौल में थी, से{विग रेट आज तक उतनी नह} हुई, 37 श्तिशत इंवेस्टमेंट रेट से बढक़र 39 श्तिशत हो गई। इस तरह से हम सब तेजी से आगे बढ़ रहे थे।

अचानक 2008–2009 के वर्ष में इस मुल्क में एक भयानक दृश्य उपस्थित हो गया। क्योंकि उस साल सरकार ने सरकारी घाटा दो लाख करोड़ से ज्यादा बढा़ दिया। एक लाख तीस हजार करोड़ बजट में था, वह बढक़र तीन लाख तीस हजार करोड़ से ऊपर चला गया। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इसी सदन में बयान दिया था कि जितना हमारा घाटा बढ़ा है, उसे आप स्टिमुलस मान लीजिए और दुनिया भर में जो फाइनेंशियल क्राइसेज आया है, उसके लिए हम स्टिमुल्स दे रहे हैं। इसलिए ये दो लाख करोड़ हमने स्टिमुलस दे दिया। अब आप देखिये कि वहां से गिरावट कैसे शुरू हुई। वर्ष 2008–2009 में फिस्कल डेफिसिट छः प्रतिशत हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट साढ़े चार प्रतिशत हो गया, उसके बाद मुद्रास्फीति की दर 4.8 प्रतिशत से बढक़र आठ प्रतिशत हो गई और तब से लगातार इस देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है। क्योंकि एक चक्रव्यूह

है, एक विशस साइकिल है। वह विशस साइकिल क्या है कि जब आपका सरकारी घाटा बढेगा और इस साल वह पांच लाख करोड़ रुपये तक गया और जब आपका घाटा बढ़ेगा तो उसका असर मुद्रास्फीति के ऊपर पड़ेगा, जब मुद्रास्फीति पर असर पड़ेगा और सरकार कुछ नहीं करेगी तो आरबीआई हरकत में आयेगा और आरबीआई उसके बाद ब्याज दर बढ़ाना शुरू करेगा। 13 बार आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ाई है। जब आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ानी शुरू की तो उसके बाद उसका नतीजा यह हुआ कि देश में जो इनवैस्टमैन्ट होता है, पूंजी निवेश होता है, उसके ऊपर उसका असर पड़ा, क्योंकि Money not only became unaffordable, it also became unavailable- न बाजार में पैसा था और जो पैसा था उसका ब्याज दर इतना था कि लोगों ने कहा कि हम इनवैस्टमैन्ट नहीं करेंगे और जब उन्होंने इनवैस्टमैन्ट नहीं किया या इनवैस्टमैन्ट करना कम कर दिया तो उसके बाद उसका असर ग्रोथ रेट पर पड़ा और जो लास्ट तिमाही के आंकडे आये हैं, यदि वह 6.1 प्रतिशत हो गया है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, अचानक कौन सी आफत आ गई। 2008–2009 में इन्होंने कहा कि दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसेज हो गया, अमरीका के बैंक कोलैप्स कर गये। उसके बाद आज कह रहे हैं कि यूरो जोन का क्राइसेज आ गया।

2008–2009 में आपने सैंटौल एक्साइज की दर (टा दी और इसे 12 श्तिशत से (टाकर आठ श्तिशत कर दिया। उस समय यह सही कदम था। आज अगर यूरो जोन का ट्राइसेज है तो आपने उसे दस से बारह श्तिशत क्यों कर दिया। हमारा कहना है कि दोनों सही नह} हो सकते। अगर यह सही है तो वह सही नह} था और अगर वह सही है तो यह सही नह} था।

2008–2009 में आपने सैंट्रल एक्साइज की दर घटा दी और इसे 12 प्रतिशत से घटाकर आठ प्रतिशत कर दिया। उस समय यह सही कदम था। आज अगर यूरो जोन का क्राइसेज है तो आपने उसे दस से बारह प्रतिशत क्यों कर दिया। हमारा कहना है कि दोनों सही नहीं हो सकते। अगर यह सही है तो वह सही नहीं था और अगर वह सही है तो यह सही नहीं था। अब क्या हो रहा है कि दोबारा इस बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा कि "I am going to be cruel in order to be kind." इस बजट का नतीजा यह हुआ कि यह 41 हजार से 42 हजार करोड़ रुपये टैक्स में उठाने जा रहे हैं। उसके साथ आप रेलवे बजट का जो बोझ है, खासकर जो फ्रेट रेट है, उसे जोड़ दीजिए तो आप पायेंगे कि इन सबका सीधा असर मुद्रास्फीति पर पड़ेगा और अर्थशास्त्र का कोई नियम यह नहीं कहता कि आप घाटा बढ़ाते जाओ और उसका असर नहीं पड़ेगा। उसका असर मुद्रास्फीति पर पड़ेगा, मुद्रास्फीति फिर तेजी से आगे बढ़ेगी और इंफ्लेशन के बारे में कहा गया है कि It is the worst form of taxation; it is taxation without legislation. सरकार को यहां आने की जरूरत नहीं है कि मुद्रास्फीति बढ़ गई है, इसलिए हम तुम्हारी मंजूरी चाहते हैं। सदन की बिना मंजूरी के यह टैक्स सरकार वसूल करेगी We are back to that vicious cycle rising inflation because of Government deficit, उसके बाद interest rate hike, lack of investment, impact of growth rate, मैं वित्त मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपके बजट ने इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कुछ नहीं किया। अगर आज मैं यहां खडे होकर दावा करूं कि जब हम लोग सरकार में थे तो हमने इस चक्रव्यूह को तोड़ दिया था।

आप यहां पर बैठे हैं और जो लोग हाँ–हाँ, कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ। आप इसे स्वीकार करें या न करें। लेकिन दुनिया इस बात को मानती है कि हम लोगों के समय में महंगाई नहीं थी। हम लोगों के समय में इंट्रेस्ट रेट को सॉफ्टन किया गया था।

अध्यक्षा जी, इसी सदन में जब सोनिया जी सुषमा जी की जगह बैठी हुई थीं तब वे हम लोगों की सरकार के लिए एक अविश्वास का प्रस्ताव लाई थीं और लास्ट डेसिबल तक कंपेयर किया था कि हमारे समय में ग्रोथ रेट क्या था, आपके समय में ग्रोथ रेट क्या था। कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ एक आंकड़ा कंपेयर कीजिए कि हमारे समय में महंगाई कितनी थी और आपके समय में महंगाई कितनी है?

अध्यक्षा जी, मैं जिस बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता था वह यह है कि इस चक्रव्यूह से हमें अपनी अर्थव्यवस्था को निकालना है। मुझे लगता है और मैं बहुत गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि वित्त मंत्री जी का जो इस साल का बजट है, वह हमें और ज्यादा इसकी गहराई में ले जाएगा। उससे हमें फायदा नहीं होने वाला है। अगर यह है तो फिर हम क्या उम्मीद करें? एक–दो बातें और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

एक तो यह है कि यहां पर जीएसटी की चर्चा हुई है। अभी हाल में राज्यों ने सेंट्रल सेल्स टैक्स का जो उनका बकाया था, उसके बारे में वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखा

कि हमारे 19 हजार करोड़ रूपये आपके ऊपर निकलते हैं, क्योंकि आपने सेंट्रल सेल्स टैक्स को 4 प्रतिशत से कम कर के 2 प्रतिशत कर दिया है और यह कहा कि हम राज्यों को कंपनसेट करेंगे। राज्यों का जो उचित मुआवजा है उसे देने के बजाय आपने उन्हें यह कह दिया कि हम 6 हजार करोड़ रूपये आपको देंगे और हमारा–तुम्हारा हिसाब साफ हो गया, अब हम राज्यों को इसके अलावा कोई पैसा नहीं देंगे। आप जानती हैं कि बिना राज्यों की सहमति के जीएसटी लागू नहीं हो सकता है। अगर जीएसटी लागू नहीं होगा तो यही सरकार कहती है कि बड़ा भारी सुधार का कदम है। तब क्या होगा? मैं एनसीटीसी और दूसरी चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर वित्तीय प्रबंधन में राज्यों के साथ नाइंसाफी की और राज्य आप से नाराज़ होते हैं तो उनसे आप इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जीएसटी लगाने में वे आपका सहयोग करेंगे। मैं आपके माध्यम से वित्तमंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि सेंट्रल सेल्स टैक्स को लेकर राज्यों का जो देय है, वह उन्हें उपलब्ध कराइए ताकि वे अपना काम–काज चला सकें। दूसरी बात, जो हमारे कई साथियों ने कही कि सारे देश का सर्राफा बाजार 12 दिनों से बंद है। जिस दिन से बजट आया है उस दिन से सर्राफा बाजार हड़ताल पर है। चाहे वह झारखण्ड का हो, अहमदाबाद का हो, चांदनी चौक का हो, हैदराबाद का हो, महाराष्ट्र का हो और चाहे गुजरात का हो, पूरे देश का सर्राफा बाजार बंद है। टैक्स लगाने का अगर कुछ अनुभव हमें है, तो मैं उस अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि इन छोटी–छोटी सर्राफा की दुकानों पर टैक्स लगा कर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ यही होगा कि आपके पदाधिकारी जाएंगे और उन लोगों को परेशान करेंगे। उसके बाद, भ्रष्टाचार का जो आलम है, जिससे हम सब परिचित हैं, उसी को बढ़ावा मिलेगा। आपको को ई–टैक्स मिलने वाला नहीं है।

इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया आपने यह जो टैक्स लगाया है, उस टैक्स को अभी, जब आप जवाब देने के लिए उठेंगे, आप फाइनेंस बिल का इंतजार मत कीजिये, आप यहीं पर घोषणा कीजिये कि आपने सर्राफा के ऊपर जो टैक्स लगाया है, उसे आप वापस ले रहे हैं। ताकि उन लाखों लोगों को रिलीफ मिल सके, जो लोग आज हड़ताल पर हैं और जिनकी रोजी–रोटी उनसे छिन गयी है, उन लोगों के लिए मैं आपसे पुरजोर सिफारिश करता हूं कि आप उन्हें राहत पहुंचायें।

मैं एक अन्तिम बात और कहना चाहता हूं, क्रुएलिटी और कोइंडनेस की बात है, आपने तो लोगों की जेब पर डाका डाला। 41 हजार करोड़ रुपया उसमें से निकाल लिया, लेकिन आपने सरकार के खर्च को काटने के लिए या कम करने के लिए क्या किया? Where is your expenditure management?

महोदया, मैं बहुत जोर देकर इस बात को कहना चाहता हूं कि सरकार में वित्त मंत्री जी ने नहीं कहा कि मंत्रियों के विदेश जाने पर हम रोक लगा रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा कि बड़े सरकारी पदाधिकारियों के विदेश जाने पर हम रोक लगा रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा कि जो ट्रैवलिंग एलाउन्स है, उसमें हम यह कटौती कर रहे हैं। उन्होंने अपने मंत्रालयों से नहीं कहा कि कागज के दोनों तरफ टाइप करो। उन्होंने पैट्रोल, डीजल आदि किसी भी चीज के बारे में नहीं कहा। ऑस्टेरिटी के बारे में इनकी बजट स्पीच में एक शब्द नहीं है। देश को आप कहते हैं कि बेल्ट बांधकर तैयार हो जाओ, टर्बोलेंट वेदर आ रहा है। पहले तो आप अपना बेल्ट बांधो। आप अपना बेल्ट नहीं बांधेंगे, आप कहेंगे सरकार का बिजनेस ऐज यूजवल है, तो देश की जनता आपकी बात क्यों मानेगी?

महोदया, बहुत सारी बातें थीं, लेकिन संक्षेप में मैं यह कह रहा हूं कि आप देश के साथ न्याय कीजिये। देश की जनता के साथ इंसाफ कीजिये और यह जो आपने एक भयानक क्रूर रूप दिखाया है, क्रूर रूप, आपका जो क्रूएल चेहरा है, वित्त मंत्री जी वह नहीं जंचता है क्योंकि आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही अच्छा लगता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कृपया मुस्कुराइये, देश की जनता को राहत पहुंचाइये। देश की जनता आपका नाम लेगी, और कोई इस सरकार में नहीं बचा, जिसमें देश की जनता को थोड़ा भी विश्वास है। अगर किसी में विश्वास है तो आपमें है, इसको बना रहने दें। ■

आप देश के साथ न्याय कीजिये। देश की जनता के साथ इंसाफ कीजिये और यह जो आपने एक भयानक क्रूर रूप दिखाया है, क्रूर रूप, आपका जो क्रूएल चेहरा है, वित्त मंत्री जी वह नहीं जंचता है क्योंकि आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही अच्छा लगता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कृपया मुस्कुराइये, देश की जनता को राहत पहुंचाइये। देश की जनता आपका नाम लेगी, और कोई इस सरकार में नहीं बचा, जिसमें देश की जनता को थोड़ा भी विश्वास है। अगर किसी में विश्वास है तो आपमें है, इसको बना रहने दें।

हमारा ध्येय है शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण : नितिन गडकरी

&lokmnkrk }kjk

Hkkरतीय जनता पार्टी का 32वां स्थापना दिवस इस बार रचनात्मक तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर 6 अप्रैल 2012 को 9 अशोक रोड, नई दिल्ली में संपन्न कार्यक्रम में 'विरासत' नाम से एक

अनूठी प्रदर्शनी लगाई गई। 'जनसंघ–भाजपा द्वारा गत 60 वर्षों में प्रकाशित दस्तावेज एवं पुस्तिकाओं' पर केन्द्रित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने किया।

इससे पूर्व एक सभा का भी आयोजन किया गया। मंच पर उपस्थित थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू, पूर्व राज्यपाल एवं वरिष्ठ नेता श्री केदारनाथ साहनी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय गोयल, राष्ट्रीय महामंत्री श्री तापिर गाव, भाजपा प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री आलोक कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री विनय सहस्रबुद्धे, मुख्यालय प्रभारी श्री ओमप्रकाश कोहली एवं दिल्ली प्रदेश भाजपाध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, सांसद एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि भाजपा एक वैचारिक दल है। राष्ट्रीय राजनीति में पार्टी का विशिष्ट स्थान है। यह देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा का काम केवल सांसद और विधायक बनाना नहीं है, अपितु हमारा उद्देश्य राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है।

उन्होंने अपने भाषण में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रेरक मार्गदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वह हर पखवाड़े उनका आशीर्वाद लेने उनके आवास पर जाते हैं।

उन्होंने कहा कि पार्टी इन दिनों 'दृष्टिपत्र–2025' दस्तावेज की तैयारी कर रही है। इसके साल के अंत में पूरा हो जाने की संभावना है। पार्टी इसे देश के मास्टर प्लान के रूप में तैयार कर रही है, जिसमें हर क्षेत्र के विकास का खाका होगा।

श्री गडकरी ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इससे जनता का विश्वास उठ गया है। चारों ओर अंधेरा है। हमें अटलजी का आशीर्वाद प्राप्त है। वर्तमान स्थिति बदलेगी। अंधेरा छंटेगा, उजाला आएगा और कमल खिलेगा। ■

दो साल में बनेगा नया पार्टी कार्यालय

श्री नितिन गडकरी ने बताया कि भाजपा का नया केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली स्थित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बनाया जाएगा। इसके लिए दो एकड़ जमीन की मंजूरी मिल चुकी है, जिस पर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। इस बहुमंजिला भवन पर 50 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस धन को दस लाख कार्यकर्ताओं के आर्थिक सहयोग से जुटाया जाएगा। इसमें अत्याधुनिक सभागार, अनुसंधान, विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बारे में ध्वनि एवं प्रकाश के माध्यम से विशेष कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। ■